सूर्योदय सुबह 5:31 बजे
सूर्यास्त शाम 7:27 बजे

www.summerexpress.in

समर एक्सप्रेस

R.N.I NO. CHMUL/25/A1155

• साल-1 • अंक-312 • पृष्ठ-8 • मूल्य-5 रूपये • वीरवार 16, जुलाई 2026 • चंडीगढ़ • पंजाब • हरियाणा • हिमाचल • ग्रुप एडिटर : अर्शदीप सिंह समर • एग्जीक्यूटिव एडिटर : नितिन उपमन्यु

न्यूज़ ब्रीफ

स्कूल बस की चपेट में आने से बच्चे की मौत

लुधियाना। लुधियाना के कोहाड़ा क्षेत्र स्थित गांव शालू में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में ढाई वर्षीय बच्चे की स्कूल बस की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। बच्चा अपनी मां के साथ बड़ी बहन को स्कूल बस में बैठाने घर के बाहर आया था। इसी दौरान बस ने उसे कुचल दिया। हादसे के बाद चालक बस लेकर भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया।

20 साल बाद पश्चिम बंगाल आएंगी तसलीमा

कोलकाता। बांग्लादेशी मूल की चर्चित लेखिका तसलीमा नसरीन करीब 20 वर्ष बाद पश्चिम बंगाल आने वाली हैं। उनका एक अगस्त को कोलकाता में आयोजित एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम है। कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लंबे समय बाद उनकी पश्चिम बंगाल यात्रा से साहित्य और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

अमृतसर में हैंड ग्रेनेड-ग्लॉक पिस्टल सहित आरोपी काबू

अमृतसर। अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 24 वर्षीय आरोपी सुमित कुमार उर्फ पंडित को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, अत्याधुनिक 9 एमएम ग्लॉक पिस्टल, चार कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

सिटीजन रिपोर्टर

अब आप भी बन सकते हैं समर एक्सप्रेस के सिटीजन रिपोर्टर। अपने इलाके की कोई भी समस्या, आयोजन, जानकारी या खबर हमें भेजें। आपके नाम के साथ प्रकाशित की जाएगी। अपनी खबर इस फोन नंबर 8699221114 या ईमेल infosummerexpress@gmail.com पर भेजें।

BOOK YOUR ADVERTISEMENT

If you want to publish your advertisement on our newspaper

समर एक्सप्रेस

CONTACT:
+91 6283 860 059

पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज, पार्टी प्रभारी ने हाईकमान को सौंपी रिपोर्ट

पंजाब कांग्रेस में घमासान बरकरार बघेल की सुलह की कोशिश नाकाम

समर न्यूज़ | चंडीगढ़/नई दिल्ली

पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर जारी अंदरूनी विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। पार्टी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल की ओर से चंडीगढ़ में असंतुष्ट नेताओं के साथ की गई बैठकों के बावजूद गतिरोध खत्म नहीं हो सका है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी है।

भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी रिपोर्ट पंजाब प्रवास के दौरान नेताओं के साथ हुई बैठकों पर आधारित है। उन्होंने नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि मैं छह दिन पंजाब में रहा। इस दौरान मैंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नेताओं से मुलाकात की और कई नेताओं के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी कीं। सभी पक्षों को सुनने और विस्तृत चर्चा के बाद मैंने अपनी रिपोर्ट एआईसीसी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है।

जब बघेल से पूछा गया कि क्या उन्होंने पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी खत्म करने के लिए प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की सिफारिश की है, तो उन्होंने जवाब देने से इन्कार करते हुए कहा मैं पार्टी नेतृत्व को दी गई अपनी रिपोर्ट की जानकारी सार्वजनिक कैसे कर सकता हूं?

उधर, विदेश दौरे से लौटने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश नेतृत्व के संकट व संगठनात्मक स्थिति पर चर्चा हुई।

इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा और उनके समर्थक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हटाने की मांग पर कायम हैं, जबकि कांग्रेस हाईकमान ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन का कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में असंतुष्ट नेताओं ने संगठन की कार्यशैली, चुनावी तैयारियों और प्रदेश नेतृत्व को लेकर अपनी आपत्तियां विस्तार से रखीं। उनका कहना है कि मौजूदा नेतृत्व में पार्टी को एकजुट करना कठिन हो रहा है और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में बदलाव आवश्यक है।

बघेल-राहुल की टीम वड़िंग पर अड़ी, बाजवा चन्नी से मिले

बताया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल व पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल नहीं चाहते थे कि राजा वड़िंग को प्रधान की कुर्सी से हटाया जाए। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बदलाव को लेकर चर्चा करने के पक्ष में हैं। इससे पहले बुधवार को हाईकमान ने अचानक विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा को दिल्ली बुलाया। बाजवा ने पंजाब लौट कर पूर्व सीएम चन्नी से मुलाकात की। बाजवा के जरिए हाईकमान ने अपना संदेश चन्नी को भेजा है।

सोशल मीडिया पर 'सारा पंजाब चन्नी दे नाल' मुहिम

इसी बीच चन्नी गुट ने भी प्रभारी के बाद कांग्रेस हाईकमान को आंखे दिखानी शुरू कर दी हैं। चन्नी गुट ने पंजाब में सोशल मीडिया पर 'सारा पंजाब चन्नी दे नाल' मुहिम शुरू की है। चन्नी गुट के नेता सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं और चन्नी के साथ होने का दावा कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि संगठनात्मक खींचतान कांग्रेस की चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकती है।

वैष्णो देवी के चढ़ावे में नकली चांदी जांच के लिए मामला अदालत पहुंचा

करीब 20 टन चांदी की शुद्धता पर उठे सवाल, अदालत ने क्राइम ब्रांच से मांगा रिकॉर्ड

एजेंसी | जम्मू

श्री माता वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई चांदी को लेकर सामने आए कथित मिलावट के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जम्मू की एक अदालत ने इस मामले में जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी को संबंधित रिकॉर्ड सहित तलब किया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मंदिर में वर्षों से जमा करीब 20 टन चांदी में बड़ी मात्रा में मिलावट पाई गई है। प्रारंभिक परीक्षण में चांदी की शुद्धता अपेक्षा से काफी कम होने की बात सामने आने के बाद मामले की जांच तेज कर दी गई है। हालांकि इन आरोपों पर अभी अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है और मामला न्यायिक विचाराधीन है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चांदी के सिक्कों और आभूषणों में कथित रूप से मिलावट, अदला-बदली अथवा गबन की आशंका है। इसी आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर व्यापक जांच की मांग की गई थी। अदालत ने क्राइम ब्रांच से अब तक की जांच का पूरा रिकॉर्ड पेश करने और जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

जांच का दायरा बढ़ा

मामले में यह भी सामने आया है कि परीक्षण के दौरान कई नमूनों में चांदी के स्थान पर कैडमियम और लोहे जैसे अन्य धातुओं की मौजूदगी पाई गई। इन दावों की पुष्टि के लिए जांच एजेंसियां दस्तावेजों, परीक्षण रिपोर्ट और पूरी प्रक्रिया की पड़ताल कर रही हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कथित मिलावट किस स्तर पर हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

श्राइन बोर्ड की भूमिका पर नजर

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं। अदालत में अगली सुनवाई के दौरान क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। इस बीच श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की नजर जांच के निष्कर्षों पर टिकी हुई है।

देश में एमबीबीएस सीटें 1.36 लाख के पार

पंजाब में 1,850 और चंडीगढ़ में 200 सीटें

एजेंसी | नई दिल्ली

देशभर के मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। भारत में एमबीबीएस की कुल सीटों की संख्या पहली बार 1.36 लाख से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की लगातार बढ़ोतरी से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश के अवसर पहले की तुलना में काफी बढ़े हैं।

सरकार का कहना है कि पिछले एक दशक में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और मौजूदा संस्थानों में सीटें बढ़ाने की नीति का सकारात्मक परिणाम सामने आया है।उत्तर भारत के राज्यों में भी सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

हरियाणा में अब 2,960 एमबीबीएस सीटें हैं, जबकि पंजाब में 1,850 और चंडीगढ़ में 200 सीटें उपलब्ध हैं। इससे इन राज्यों के छात्रों के साथ-साथ अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मेडिकल शिक्षा में अधिक अवसर मिलने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीटें बढ़ने से प्रतिस्पर्धा पूरी तरह समाप्त नहीं होगी, लेकिन योग्य छात्रों के लिए प्रवेश की संभावनाएं पहले से बेहतर होंगी।

▪ **चिकित्सा ढांचे को मिलेगा बल:** *स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से भविष्य में डॉक्टरों की उपलब्धता में सुधार होगा। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य देश में प्रति व्यक्ति डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार करना है।*

▪ **नीट अभ्यर्थियों को होगा लाभ:** *नीट के माध्यम से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को बढ़ी हुई सीटों का सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मेडिकल शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पर्याप्त फैकल्टी, अस्पतालों में प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार भी उतना ही आवश्यक है।*

गडकरी बोले- 100% पेट्रोल चाहिए तो अधिक कीमत चुकानी होगी

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कहा- ई20 स्वच्छ ईंधन, शुद्ध पेट्रोल की अलग आपूर्ति से बढ़ेगी लागत; सरकार ने भी दी सफाई

एजेंसी | नई दिल्ली

ई20 पेट्रोल को लेकर जारी बहस के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यदि कोई उपभोक्ता 100 प्रतिशत शुद्ध पेट्रोल खरीदना चाहता है तो उसे इसके लिए अधिक कीमत चुकानी होगी।

उन्होंने कहा कि ई20 (20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) देश की ऊर्जा सुरक्षा, प्रदूषण में कमी और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही उन्होंने यह भी माना कि कुछ वाहनों में माइलेज पर मामूली असर पड़ सकता है, लेकिन इंजन को नुकसान पहुंचने संबंधी दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। सोशल मीडिया पर बहस जारी है।

सरकार ने दिया तकनीकी पक्ष

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि ई20 ईंधन व्यापक परीक्षणों के बाद लागू किया गया है। मंत्रालय के अनुसार इथेनॉल मिश्रण से विदेशी मुद्रा की बचत, किसानों को लाभ और कार्बन उत्सर्जन में कमी जैसे कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। सरकार का कहना है कि पुराने वाहनों के उपयोगकर्ताओं की चिंताओं पर भी नजर रखी जा रही है और वाहन निर्माताओं के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ई20 को लेकर उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने और तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने से भ्रम की स्थिति काफी हद तक दूर हो सकती है।

भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता अमृतसर से पहली खेप रवाना

एजेंसी | नई दिल्ली

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रेडीमेड परिधानों की पहली निर्यात खेप बुधवार को रवाना की गई।

अधिकारियों ने इसे पंजाब के निर्यात क्षेत्र और वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस पहल से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय परिधानों की पहुंच बढ़ने के साथ पंजाब के निर्यातकों को नए व्यावसायिक अवसर मिलने की उम्मीद है। उद्योग जगत का मानना है कि भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते से सीमा शुल्क में मिलने वाली रियायतों का लाभ निर्यातकों को मिलेगा। इससे विशेष रूप से रेडीमेड गारमेंट्स, वस्त्र और एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती मिलने की संभावना है। निर्यातकों ने कहा कि अमृतसर एयरपोर्ट से सीधे कार्गो भेजे जाने से समय व लागत में कमी आएगी।

वांगचुक के अनशन पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जनहित याचिका में वांगचुक को तुरंत मेडिकल सुविधा और इलाज देने की मांग

एजेंसी | नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को बहुत जरूरी माना। केंद्र और दिल्ली सरकार से गुरुवार सुबह तक जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट ने यह सुनवाई एक जनहित याचिका पर की। इसमें वांगचुक को तुरंत मेडिकल सुविधा और इलाज देने की मांग की गई है। वांगचुक नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 18 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। उनकी हालत गिरती जा रही है। 8:50 किग्रा तक वजन गिर गया है। कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के विरोध में 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

अगस्त के शुरु में बुलाया जा सकता है पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र

समर न्यूज़ | चंडीगढ़

पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त के पहले सप्ताह में बुलाए जाने की संभावना है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सत्र में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी से जुड़े कानून में संशोधन का विधेयक सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।

राज्य से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विधायी और वित्तीय विषयों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। सरकार संशोधित कानून को अधिक प्रभावी और कानूनी रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से आवश्यक बदलावों पर विचार कर रही है। राज्य सरकार सत्र के एजेंडे को अंतिम रूप देने में जुटी है। विभिन्न विभागों से प्रस्तावित विधेयकों और लंबित विषयों की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि उन्हें विधानसभा में पेश किया जा सके।

विपक्षी दलों ने संकेत दिए हैं कि वे कानून-व्यवस्था, कृषि, वित्तीय स्थिति और जनहित से जुड़े मुद्दों को सत्र में प्रमुखता से उठाएंगे। ऐसे में मानसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है।

पेज 1 एंकर स्टोरी

ओडिशा के साथ पश्चिम बंगाल की पारंपरिक जगन्नाथ यात्राओं को भी मिल रही पहचान

पुरी रथयात्रा आज से: छह महीने पहले से होटल बुक, किराए में कई गुना उछाल

एजेंसी | पुरी

भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा वीरवार से शुरू होगी। ओडिशा के पुरी में तैयारियां तेज हो गई हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने के लिए देश-विदेश से पहुंचते हैं। इसी वजह से इस बार भी रथयात्रा से कई महीने पहले ही अधिकांश होटल, धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस बुक हो चुके हैं।

पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि मांग बढ़ने के कारण प्रमुख स्थानों पर कमरों के किराए में कई गुना वृद्धि देखी जा रही है। सामान्य दिनों में लगभग 1,500 रुपये प्रतिदिन में मिलने वाले कुछ कमरे रथयात्रा के दौरान 30 हजार से 50 हजार रुपये तक में बुक होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि प्रशासन ने होटल संचालकों को निर्धारित नियमों और पारदर्शी बुकिंग व्यवस्था का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

रथयात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के विशाल रथ श्रीमंदिर से गुंडिचा मंदिर तक खींचे जाते हैं। इस परंपरा को देखने के लिए हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल, यातायात और आपदा प्रबंधन के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। रेलवे ने भी अतिरिक्त ट्रेनों की योजना बनाई है, जबकि सड़क और बस सेवाओं को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है।

हावड़ा की अनूठी परंपरा भी चर्चा में

पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी जगन्नाथ रथयात्रा की एक अनोखी परंपरा लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। यहां कुछ स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को श्रद्धालु गोद में लेकर शोभायात्रा निकालते हैं। स्थानीय मान्यताओं और सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ी यह यात्रा धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक सहभागिता का भी प्रतीक मानी जाती है। बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु और पर्यटक इस आयोजन में भाग लेते हैं। धार्मिक विशेषज्ञों के अनुसार, भारत के विभिन्न राज्यों में जगन्नाथ रथयात्रा स्थानीय परंपराओं के अनुरूप अलग-अलग स्वरूप में आयोजित की जाती है, लेकिन सभी आयोजनों का मूल उद्देश्य भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा और सामाजिक समरसता का संदेश देना है।

प्रशासन की अपील और तैयारी

पुरी जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से केवल अधिकृत माध्यमों से होटल बुकिंग करने और अत्यधिक किराया वसूलने की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों को सूचना देने की अपील की है। साथ ही ऑनलाइन बुकिंग के दौरान होटल की वैधता और शर्तों की जांच करने की भी सलाह दी गई है। प्रशासन का कहना है कि रथयात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक सुदृढ़ रहेगी। भीड़ नियंत्रण, निगरानी, चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सेवाओं के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन का अनुभव मिल सके।

गैंगस्टर, नशा तस्करी और आतंकवाद पर संयुक्त प्रहार पंजाब सहित पांच राज्यों व एनआईए की साझा रणनीति

सूचना साझा करने, समन्वित अभियान और सीमा पार नेटवर्क पर कार्रवाई तेज करने पर बनी सहमति

समर न्यूज। चंडीगढ़

देश में गैंगस्टर नेटवर्क, मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के बढ़ते गठजोड़ से निपटने के लिए पांच राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने संयुक्त रणनीति पर सहमति बनाई है।

हाल ही में हुई बैठक में विभिन्न राज्यों की पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और सुरक्षा अधिकारियों ने आपसी समन्वय बढ़ाने, खुफिया सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान और संयुक्त अभियानों को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। अधिकारियों का मानना है कि संगठित अपराध, नशा तस्करी और आतंकवाद के बीच बढ़ते संबंधों को देखते हुए राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। बैठक में विशेष रूप से पंजाब और सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय नेटवर्क, विदेशों में बैठे गैंगस्टरों के मॉड्यूल, हवाला के जरिए होने वाली फंडिंग और ड्रोन के माध्यम से हथियार एवं मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मामलों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने सीमा पार से संचालित आपराधिक और आतंकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने तथा तकनीकी और वित्तीय जांच को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की।

संयुक्त अभियान पर जोर

बैठक में तय किया गया कि राज्यों की पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी नियमित रूप से सूचनाएं साझा करेंगी और आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त अभियान चलाए जाएंगे। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, संपत्तियों की पहचान और अवैध वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई को भी प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साइबर माध्यमों से संचालित आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

सीमावर्ती राज्यों पर विशेष फोकस

अधिकारियों के अनुसार, सीमावर्ती राज्यों में नशा तस्करी और आतंकवाद से जुड़े मामलों को देखते हुए समन्वित कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि साझा रणनीति से अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। पंजाब में नशे का नेटवर्क तोड़ने पर विशेष काम होगा।

नंगल के 14 गांवों का राजस्व रिकॉर्ड हुआ गायब भाजपा नेता ने राज्यपाल से की हस्तक्षेप की मांग

भूमि अभिलेखों के लापता होने पर निष्पक्ष जांच की मांग, किसानों की चिंता बढ़ी

समर न्यूज। चंडीगढ़

पंजाब के रूपनगर जिले के नंगल क्षेत्र के 14 गांवों का राजस्व रिकॉर्ड कथित रूप से गायब होने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मदन मोहन मित्तल ने इस मामले में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व अभिलेखों के गायब होने से हजारों किसानों और जमीन मालिकों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं तथा पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।

भाजपा नेता ने राज्यपाल से दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और लापता रिकॉर्ड का जल्द पता लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते अभिलेख बरामद नहीं हुए तो भविष्य में भूमि संबंधी विवाद और कानूनी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

दूसरी ओर, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है।

ग्रामीणों में बढ़ी चिंता

ग्रामीणों और किसानों ने भी राजस्व रिकॉर्ड सुरक्षित रखने तथा पूरे मामले में पारदर्शिता बरतने की मांग की है। उनका कहना है कि जमीन संबंधी दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और प्रशासन की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

पंजाब के आठ टोल प्लाजा पर शुल्क में बढ़ोतरी लाडोवाल टोल चार महीने में दूसरी बार महंगा

सिंगल यात्रा पर 60 रुपये तक की बढ़ोतरी, मासिक पास और अन्य श्रेणियों के शुल्क भी संशोधित

समर न्यूज। चंडीगढ़

पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित आठ टोल प्लाजा पर टोल शुल्क बढ़ा दिया गया है। संशोधित दरें लागू होने के बाद सबसे अधिक चर्चा लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा की हो रही है, जहां चार महीने के भीतर दूसरी बार शुल्क में वृद्धि की गई है।

नई दरों के अनुसार, कुछ श्रेणियों के वाहनों के लिए एकल यात्रा (सिंगल जर्नी) का शुल्क 60 रुपये तक बढ़ गया है। इसके अलावा मासिक पास, वापसी यात्रा और वाणिज्यिक वाहनों की दरों में भी संशोधन किया गया है।

स्थानीय वाहन चालकों, ट्रांसपोर्टरों और व्यापारिक संगठनों ने लगातार बढ़ रहे टोल शुल्क पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि बार-बार बढ़ोतरी से परिवहन लागत बढ़ेगी, जिसका असर माल ढुलाई और आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। दूसरी ओर, टोल प्रबंधन का कहना है कि संशोधित दरें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निर्धारित नियमों के अनुसार लागू की गई हैं।

परिवहन लागत बढ़ने की आशंका: विशेषज्ञों का मानना है कि टोल शुल्क में वृद्धि से लंबी दूरी के परिवहन और दैनिक आवागमन करने वाले लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

ट्रांसपोर्ट संगठनों ने सरकार से बढ़ी हुई दरों की समीक्षा कर राहत देने की मांग की है। फिलहाल नई दरें सभी संबंधित टोल प्लाजा पर प्रभावी हो चुकी हैं।

गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का करीबी एफबीआई की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल

समर न्यूज। चंडीगढ़

पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के कथित करीबी नीतिश का नाम अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया गया है।

अमेरिकी जांच एजेंसी के अनुसार नीतिश पर हत्या, अवैध हथियारों की आपूर्ति और संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। मामले में अमेरिकी अदालत से उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी एजेंसियां नीतिश की तलाश में जुटी हैं और उसके संभावित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की भी जांच कर रही हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर मामले पर नजर बनाए हुए हैं।

जांच एजेंसियों का कहना है कि यदि आवश्यक हुआ तो कानूनी प्रक्रियाओं के तहत अंतरराष्ट्रीय सहयोग लिया जाएगा। फिलहाल एफबीआई की ओर से जारी वारंट के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, जबकि मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

फिरोजपुर: 17.35 लाख की जाली भारतीय करेंसी जब्त

समर न्यूज। फिरोजपुर: फिरोजपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 17 लाख 35 हजार रुपये की जाली भारतीय मुद्रा बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी इस नकली करेंसी की खेप को कहीं पहुंचाने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारी सुखविंदर सिंह ने बताया कि थाना कैंट क्षेत्र में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए बाइक सवार दो संदिग्ध युवकों को रोका गया। जांच के दौरान उनके पास से जाली भारतीय नोट बरामद हुए।

एसआईआर के शेडयूल में बदलाव, अब 3 अगस्त तक होगी वेरिफिकेशन

समर न्यूज। चंडीगढ़

भारत निर्वाचन आयोग ने पंजाब में वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। 1 अक्टूबर, 2026 की पात्रता तारीख के आधार पर होने वाले इस रिवीजन को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब को नए आदेश भेज दिए गए हैं।

नए कार्यक्रम के तहत अब राज्य में पोलिंग स्टेशनों के पुनर्गठन से लेकर फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन तक की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब बीएलओ 3 अगस्त तक लोगों के घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद 13 अगस्त को नई वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी होगा, जिस पर लोग 12 सितंबर तक अपने नाम जुड़वाने या सुधार करवाने के लिए दावे और आपत्तियां दे सकेंगे। सभी सुधारों को पूरा करने के बाद 12 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी।

इंग्लैंड में पंजाबी युवती की हत्या तरनतारन की बेटी पर चाकू से हमला

▪ सीसीटीवी में संदिग्ध हाथ में चाकू लिए दिखा, ब्रिटिश पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज की

एजेंसी। लंदन

इंग्लैंड में पंजाब के तरनतारन जिले की एक युवती की चाकू मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, हमलावर ने युवती के पेट पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध व्यक्ति हाथ में चाकू लिए घटनास्थल के पास दिखाई दिया है। ब्रिटिश पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार, युवती को बेहतर भविष्य की उम्मीद में उसके पिता ने जमीन बेचकर इंग्लैंड भेजा था।

परिवार गहरे सदमे में है और उन्होंने भारत सरकार तथा ब्रिटेन प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ब्रिटिश पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: दो आरोपियों को जेल से ले गई पुलिस, पूछताछ में खोले जाएंगे राज

चोरी की रकम, छिपाने की जगह और वारदात के तरीके की होगी जांच; सीईओ पद के लिए 24 घंटे में 1000 से ज्यादा आवेदन

एजेंसी। अयोध्या

अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की रकम चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों को पुलिस ने जेल से अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि मंदिर से पैसे चोरी करने की योजना कैसे बनाई गई, कितनी रकम गायब की गई और चोरी के बाद उसे कहां छिपाया गया या खर्च किया गया।

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों से वारदात से जुड़े सभी पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या आरोपियों ने अकेले ही पूरी घटना को अंजाम दिया। पुलिस चोरी की रकम की बरामदगी को प्राथमिकता दे रही है।

सूत्रों के मुताबिक, मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और चढ़ावे की रकम की निगरानी से जुड़े पहलुओं की भी समीक्षा की जा रही है। जांच एजेंसियां आरोपियों के मोबाइल रिकॉर्ड, संपर्कों और आर्थिक लेन-देन की जानकारी भी जुटा सकती हैं, ताकि मामले की पूरी कड़ी सामने आ सके।

▪ **सीईओ पद के लिए आवेदनों की बाढ़** : राम मंदिर से जुड़े एक महत्वपूर्ण पद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने रुचि दिखाई है। जानकारी के अनुसार, 24 घंटे के भीतर ही करीब 1000 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

ट्रस्ट की ओर से पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन तय प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। सीईओ पद के लिए प्रशासनिक अनुभव, प्रबंधन क्षमता और धार्मिक संस्थानों के संचालन की समझ रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। आवेदन आने के बाद अब ट्रस्ट स्तर पर उनकी छंटनी और आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

▪ **सुरक्षा और व्यवस्था पर फोकस:** राम मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्रस्ट और प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं को मजबूत करने में जुटे हैं। चढ़ावे की रकम और अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी को लेकर सुरक्षा उपायों को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चोरी मामले में जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि वारदात में कितनी रकम शामिल थी और इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की भूमिका थी या नहीं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है।

भोजशाला परिसर के पास शुक्रवार को नमाज, सुरक्षा बढ़ाई

एजेंसी। धार

मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर के पास शुक्रवार को नमाज अदा की गई। धार्मिक और पुरातात्विक महत्व वाले इस क्षेत्र को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरे क्षेत्र में निगरानी करते रहे।

प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की।

नमाज की प्रक्रिया निर्धारित व्यवस्था के तहत संपन्न कराई गई। भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के अलग-अलग दावे रहे हैं। हिंदू पक्ष इसे मां वाग्देवी का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है।

पति की सैलरी का 25% गुजारा भत्ता तय करना अनिवार्य नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट

कहा- भरण-पोषण की राशि तय करते समय आय के साथ अन्य परिस्थितियों पर भी देना होगा ध्यान

एजेंसी। प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति की कुल आय का 25 प्रतिशत हिस्सा गुजारा भत्ता (भरण-पोषण) के रूप में देना कोई अनिवार्य नियम नहीं है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण की राशि तय करते समय पति की आय के अलावा पत्नी की जरूरतों, दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति और अन्य परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अदालत ने कहा कि हर मामले में एक समान प्रतिशत तय नहीं किया जा सकता। न्यायालयों को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित राशि निर्धारित करनी चाहिए।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भरण-पोषण का उद्देश्य जरूरतमंद पक्ष को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है, न कि किसी एक पक्ष पर असंतुलित आर्थिक बोझ डालना। इसलिए राशि तय करते समय सभी पहलुओं का संतुलन बनाया जाना चाहिए।

अदालत ने यह भी माना कि कई मामलों में पति की आय के एक निश्चित प्रतिशत को आधार बनाया जाता है, लेकिन इसे बाध्यकारी फार्मूला नहीं माना जा सकता। प्रत्येक वैवाहिक विवाद में अलग-अलग परिस्थितियां होती हैं, जिनके आधार पर फैसला लिया जाना चाहिए।

दिव्यांगों पर टिप्पणी मामला: कॉमेडियन समय रैना समेत 5 पर जुर्माना

एजेंसी। नई दिल्ली

दिव्यांगों और अन्य संवेदनशील वर्गों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना समेत पांच लोगों पर जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति या समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाई जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत ने संबंधित लोगों को सुधार का अवसर दिया था, लेकिन स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं आया। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि उसे गुमराह करने की कोशिश की गई। अदालत ने कहा कि संविधान सभी को बोलने की आजादी देता है, लेकिन इस अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। मनोरंजन के नाम पर किसी की शारीरिक स्थिति या पहचान का मजाक उड़ाना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

दुष्कर्म मामले में पटना हाई कोर्ट की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज

▪ शीर्ष अदालत ने कहा- संवेदनशील मामलों में न्यायिक टिप्पणियों में सावधानी जरूरी, पीड़िता की गरिमा सर्वोपरि

एजेंसी। नई दिल्ली

दुष्कर्म के एक मामले में पटना हाई कोर्ट की टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों में अदालतों को बेहद संवेदनशीलता और सावधानी के साथ टिप्पणियां करनी चाहिए।

पीड़िता की गरिमा और अधिकारों की रक्षा न्याय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यौन अपराधों के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य पीड़िता को न्याय दिलाना और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों की टिप्पणियों का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

इसलिए संवेदनशील मामलों में ऐसी भाषा से बचना चाहिए, जिससे पीड़िता या उसके परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचे या गलत संदेश जाए। शीर्ष अदालत ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड और हाई कोर्ट के आदेश पर विचार किया।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया और पीड़िता के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी।

पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, गोला-बारूद बरामद

राजौरी में दो संदिग्ध आतंकियों की सूचना के बाद तलाशी अभियान तेज, सेना और सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा

एजेंसी। जम्मू

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने का पता लगाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों को भारी मात्रा में गोला-बारूद और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। अधिकारियों के अनुसार, बरामद सामग्री से यह संकेत मिले हैं कि आतंकी किसी बड़ी वारदात की तैयारी में हो सकते थे। सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया था। अभियान के दौरान संदिग्ध ठिकाने की पहचान हुई, जिसके बाद वहां से हथियारों से संबंधित सामान और अन्य सामग्री बरामद की गई। सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह ठिकाना किन आतंकियों से जुड़ा था और यहां तक सामग्री कैसे पहुंची। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है।

राजौरी में संदिग्ध गतिविधि की सूचना

इधर, जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में दो संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया है। सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीमें इलाके में घर-घर तलाशी और जंगल क्षेत्रों में जांच कर रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक, संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है। ड्रोन और अन्य निगरानी उपकरणों की मदद से भी इलाके पर नजर रखी जा रही है।

सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई

सुरक्षा एजेंसियां पुंछ और राजौरी जैसे सीमावर्ती जिलों में लगातार अभियान चला रही हैं। इन क्षेत्रों में घुसपैठ और आतंकी नेटवर्क को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान पूरा होने के बाद ही स्थिति की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। फिलहाल दोनों जिलों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है।

प्राइमरी स्कूल से बच्चों को उम्र के अनुसार दी जाएगी सेक्स एजुकेशन

एजेंसी। नई दिल्ली

देश में बच्चों को कम उम्र से ही उम्र और समझ के अनुसार यौन शिक्षा देने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में गठित 26 सदस्यीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं से ही बच्चों को सुरक्षित व्यवहार, शरीर में होने वाले बदलाव, व्यक्तिगत सुरक्षा और अच्छे-बुरे स्पर्श जैसी जानकारियां देने का सुझाव दिया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों को दी जाने वाली जानकारी उनकी उम्र और मानसिक विकास के अनुरूप होनी चाहिए। इसके लिए स्कूलों में सप्ताह में दो बार करीब 20 मिनट की विशेष कक्षाएं आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है। पैनल ने शिक्षकों को भी इसके लिए प्रशिक्षित करने की जरूरत बताई है, ताकि विषय को संवेदनशील और वैज्ञानिक तरीके से समझाया जा सके। पैनल का मानना है कि सही समय पर दी गई जानकारी बच्चों को गलत सूचनाओं और शोषण से बचाने में मदद कर सकती है। रिपोर्ट में किशोरावस्था, स्वास्थ्य, स्वच्छता और व्यक्तिगत सीमाओं से जुड़े विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश की गई है।

▪ **अभिभावकों की भागीदारी जरूरी:** रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की शिक्षा को लेकर अभिभावकों और समाज में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों को सही जानकारी देने से वे अपनी सुरक्षा को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि, इस विषय पर अंतिम निर्णय संबंधित शिक्षा विभाग और सरकार की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा।

समर प्राइम 3
www.summerexpress.in
16 जुलाई 2026
समर एक्सप्रेस

नहीं थम रहा बम की धमकियों का सिलसिला, आरोपी पहुंच से दूर

स्कूलों से सरकारी दफ्तरों तक दहशत, लगातार मिल रहे धमकी भरे ई-मेल और संदेशों ने बढ़ाई चिंता

समर न्यूज़। चंडीगढ़

पंजाब और चंडीगढ़ में पिछले कुछ महीनों से स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अधिकांश मामलों में जांच के बाद कोई विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन हर बार सुरक्षा एजेंसियों को बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाना पड़ा।

इससे न केवल प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा, बल्कि हजारों विद्यार्थियों, अभिभावकों और कर्मचारियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हाल के दिनों में मोहाली के तीन निजी स्कूलों और मेयर कार्यालय को ई-मेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे ट्राईसिटी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।

पुलिस, बम निरोधक दस्तों, डॉग स्क्वायड और साइबर विशेषज्ञों ने घंटों तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन किसी भी स्थान से विस्फोटक नहीं मिला। प्रारंभिक जांच में इन धमकियों को फर्जी माना गया, फिर भी पुलिस ने इन्हें गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी।

विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं अब केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं रह गई हैं, बल्कि यह साइबर अपराध, मनोवैज्ञानिक दबाव और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा बहुआयामी मुद्दा बन चुकी हैं। पुलिस रिकॉर्ड और विभिन्न मामलों की जांच से पता चलता है कि अधिकांश धमकियां ई-मेल, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन), अस्थायी ई-मेल आईडी अथवा विदेशी सर्वर के माध्यम से भेजी जाती हैं। कई मामलों में प्रेषक अपनी डिजिटल पहचान छिपाने के लिए तकनीकी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी पहचान करना काफी कठिन हो जाता है।

कई ई-मेल ऐसे सर्वरों से भेजे गए हैं जिनका संबंध विदेशों से जुड़ा दिखाई देता है। ऐसे मामलों में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में समय लगता है।

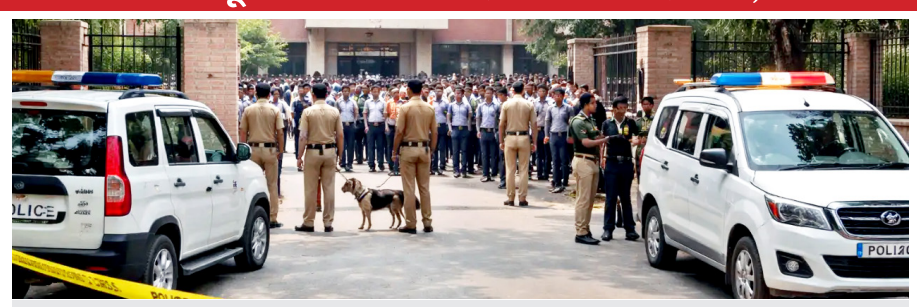

स्कूलों पर सबसे अधिक असर, मानसिक स्वास्थ्य व शिक्षा पर असर

इन धमकियों का सबसे बड़ा प्रभाव स्कूलों और विद्यार्थियों पर पड़ा है। जैसे ही किसी स्कूल को धमकी मिलती है, तत्काल कक्षाएं रोक दी जाती हैं। विद्यार्थियों को मैदान या सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाता है। अभिभावकों को तत्काल सूचना भेजी जाती है और कई बार बच्चों को समय से पहले घर भेजना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान परीक्षा, प्रयोगशाला कार्य, खेल गतिविधियां और नियमित पढ़ाई प्रभावित होती है। कई अभिभावकों का कहना है कि लगातार ऐसी घटनाओं से बच्चों में भय का माहौल बन रहा है। छोटे बच्चों में स्कूल जाने को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। शिक्षाविदों का मानना है कि यदि यह सिलसिला लंबे समय तक जारी रहा तो इसका असर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर पड़ सकता है।

धमकियों के बाद स्कूलों ने बदले सुरक्षा प्रोटोकॉल

लगातार मिल रही धमकियों के बाद कई निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है। अनेक स्कूलों में प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। आगंतुकों की पहचान की प्रक्रिया सख्त की गई है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाई गई है और आपातकालीन निकासी अभ्यास (मॉक ड्रिल) भी कराए जा रहे हैं। कुछ स्कूलों ने अभिभावकों के साथ त्वरित संवाद के लिए विशेष डिजिटल अलर्ट प्रणाली भी विकसित की है। पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस और जिला प्रशासन का कहना है कि किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लिया जाता। सूचना मिलते ही संबंधित परिसर को खाली कराया जाता है और विशेषज्ञ टीमों द्वारा व्यापक तलाशी ली जाती है। अधिकारियों का कहना है कि साइबर जांच भी समानांतर रूप से जारी रहती है और प्रत्येक डिजिटल साक्ष्य का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है।

अभिभावकों की बढ़ी चिंता

मोहाली, चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले अभिभावकों का कहना है कि हर बार स्कूल से अचानक आने वाला संदेश उन्हें चिंता में डाल देता है। कई माता-पिता अपने बच्चों को लेने के लिए तत्काल स्कूल पहुंच जाते हैं, जिससे स्कूलों के बाहर भारी भीड़ लग जाती है। अभिभावकों की मांग है कि सरकार केवल जांच तक सीमित न रहे बल्कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दीर्घकालिक रणनीति भी तैयार करे।

सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती

हर धमकी के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड, अग्निशमन विभाग और स्थानीय प्रशासन को तत्काल सक्रिय होना पड़ता है। किसी भी खतरे की संभावना को देखते हुए पूरे परिसर की विस्तृत तलाशी ली जाती है। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि भले ही अधिकांश धमकियां झूठी साबित हुई हों, लेकिन किसी भी सूचना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यदि एक भी सूचना वास्तविक निकली तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसी कारण प्रत्येक कॉल, ई-मेल या संदेश को समान गंभीरता के साथ लिया जाता है। इन मामलों में सबसे बड़ी चुनौती ई-मेल भेजने वाले व्यक्ति तक पहुंचना है। साइबर अपराध विशेषज्ञों के अनुसार यदि अपराधी वीपीएन, प्रॉक्सी सर्वर, टेम्परेरी ई-मेल सेवा और विदेशी डोमेन का इस्तेमाल करता है तो उसकी वास्तविक पहचान तक पहुंचने में काफी समय लग सकता है। जांच एजेंसियों को कई बार अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से तकनीकी जानकारी मांगनी पड़ती है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आवश्यक डाटा उपलब्ध हो पाता है। यही कारण है कि कई मामलों में महीनों बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहते हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल सहयोग बढ़ाने की जरूरत

लगातार सामने आ रही घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल तलाशी अभियान चलाना पर्याप्त नहीं होगा। साइबर अपराधियों तक शीघ्र पहुंच बनाने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल सहयोग बढ़ाने, स्कूलों की सुरक्षा प्रणाली मजबूत करने और झूठी धमकियां देने वालों के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। जब तक इन मामलों के पीछे छिपे लोगों की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में नहीं लाया जाता, तब तक प्रत्येक नई धमकी विद्यार्थियों, अभिभावकों और आम नागरिकों के मन में भय और असुरक्षा की भावना पैदा करती रहेगी। सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती केवल हर बार तलाशी अभियान चलाने की नहीं, बल्कि इस सिलसिले पर स्थायी रोक लगाने की भी है।

अस्पतालों, हवाई अड्डों, अदालतों को भी मिलीं धमकियां

देश के कई राज्यों में पिछले डेढ़-दो वर्षों के दौरान स्कूलों, अस्पतालों, हवाई अड्डों, अदालतों और सरकारी कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने के अनेक मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और चंडीगढ़ सहित कई शहर इससे प्रभावित रहे हैं। अधिकांश मामलों में तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन इन घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था की नई चुनौतियों को सामने ला दिया। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार बम की झूठी सूचना देना भी गंभीर अपराध है। इससे दहशत फैलती है, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है और लोगों के सामान्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता तथा सूचना प्रौद्योगिकी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दोष सिद्ध होने पर कठोर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है।

विशेषज्ञ बोले- पारंपरिक पुलिसिंग पर्याप्त नहीं

आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऐसे मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए केवल पारंपरिक पुलिसिंग पर्याप्त नहीं होगी। उनके अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ई-मेल विश्लेषण, उन्नत साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाएं, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय और स्कूलों के लिए एकीकृत सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित करना समय की आवश्यकता है। विशेषज्ञ यह भी सुझाव देते हैं कि विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि अफवाहों से बचा जा सके और किसी भी आपात स्थिति में व्यवस्थित ढंग से कार्रवाई हो सके। हर झूठी धमकी के साथ पुलिस बल का बड़ा हिस्सा कई घंटों तक एक ही स्थान पर तैनात रहता है। इससे अन्य क्षेत्रों में नियमित पुलिस व्यवस्था भी प्रभावित होती है। यातायात रोकना पड़ता है, कार्यालयों का काम बाधित होता है और आपात सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आसपास के बाजारों में भी कुछ समय के लिए गतिविधियां प्रभावित होती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल सुरक्षा का नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का भी विषय है।

अधूरी सड़कें, खुली नालियां और मानसून की मार, बारिश के बाद जलभराव, दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम का बढ़ा खतरा

मोहाली की विकास परियोजनाएं बनीं निवासियों की परेशानी का कारण

खरड़-लांडरां रोड से लेकर फेज-9, बलौंगी और अन्य इलाकों में ज्यादातर निर्माण कार्य अधूरा

समर न्यूज़। मोहाली

मोहाली देश के तेजी से विकसित हो रहे शहरों में गिना जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रियल एस्टेट के क्षेत्र में लगातार विस्तार के कारण यहां आबादी और वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लेकिन शहर की विकास परियोजनाओं की धीमी रफ्तार अब आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। मानसून के बीच अधूरी सड़क परियोजनाएं, खुली नालियां, उखड़ी सड़कें, अधूरा सीवरेज कार्य और जल निकासी की कमजोर व्यवस्था लोगों की चिंता का प्रमुख कारण बन गई है।

विशेष रूप से खरड़-लांडरां रोड, फेज-9 के आसपास, बलौंगी, संभालखी-नानूमाजरा मार्ग और कुछ अन्य क्षेत्रों में निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं होने से स्थानीय लोगों, व्यापारियों और रोजाना आने-जाने वाले हजारों वाहन चालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हाल के दिनों में हुई बारिश के बाद कई स्थानों पर पानी भर गया, जिससे सड़कों की वास्तविक स्थिति और भी खराब दिखाई दी।

मानसून शुरू होने से पहले नगर निगम और संबंधित एजेंसियों ने नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था सुधारने और सड़क मरम्मत के दावे किए थे। लेकिन पहली ही बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव की तस्वीरें सामने आने लगीं। कई इलाकों में बारिश का पानी घंटों तक जमा रहा। इससे न केवल यातायात प्रभावित हुआ बल्कि दोपहिया वाहन चालकों, पैदल चलने वालों और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ी।

मोहाली और खरड़ को जोड़ने वाला खरड़-लांडरां मार्ग ट्राईसिटी के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल है। इसी सड़क से प्रतिदिन हजारों निजी वाहन, स्कूल बसें, सार्वजनिक परिवहन और मालवाहक वाहन गुजरते हैं। पिछले कई महीनों से इस सड़क पर सीवरेज और अन्य आधारभूत ढांचे के कार्य चल रहे हैं। हालांकि कुछ हिस्सों में मरम्मत का काम हुआ है, लेकिन कई स्थानों पर सड़क अभी भी अधूरी है। कहीं सड़क उखड़ी हुई है, कहीं एक तरफ खुदाई है तो कई जगह नालियां खुली छोड़ दी गई हैं। भारी बारिश होने पर यही स्थान सबसे अधिक जोखिम वाले बन जाते हैं।

परियोजनाओं में देरी के कारण

निर्माण क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार बड़ी परियोजनाओं में देरी के कई कारण हो सकते हैं। इनमें भूमि संबंधी विवाद, तकनीकी स्वीकृतियां, बजट संबंधी प्रक्रियाएं, मौसम की बाधाएं और ठेकेदार स्तर की चुनौतियां शामिल हैं। हालांकि नागरिकों का कहना है कि कारण चाहे जो भी हों, उसका असर आम लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए संबंधित एजेंसियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करना चाहिए। बरसात के दौरान सड़क किनारे बने गड्ढे, खुले मैनहोल और अधूरी नालियां दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं। यातायात विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे स्थानों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा बैरिकेड लगाए जाने चाहिए। दोपहिया वाहन चालकों के लिए जोखिम सबसे अधिक होता है क्योंकि बारिश के दौरान सड़क की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है।

जनप्रतिनिधियों ने उठाई मांग

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने समय-समय पर अधूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि मोहाली जैसे तेजी से बढ़ते शहर में आधारभूत ढांचे की समस्याओं का शीघ्र समाधान जरूरी है। कई संगठनों ने परियोजनाओं की नियमित सार्वजनिक समीक्षा और प्रगति रिपोर्ट जारी करने की भी मांग की है ताकि लोगों को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि मोहाली की समस्याओं का समाधान केवल अस्थायी मरम्मत से नहीं होगा। शहर को दीर्घकालिक दृष्टि से सड़क, सीवरेज और जल निकासी प्रणाली को मजबूत करना होगा। साथ ही निर्माण एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी सुनिश्चित करनी होगी। यदि अधूरी सड़क परियोजनाओं, खुली नालियों और जल निकासी संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी और यातायात के साथ चुनौतियां और गंभीर हो सकती हैं।

लोगों की उम्मीदः परेशानियों से जल्द मिलेगी राहत

मोहाली के नागरिक विकास कार्यों का विरोध नहीं करते। उनकी मुख्य मांग यह है कि जो परियोजनाएं शुरू की जाएं, उन्हें तय समय सीमा में पूरा किया जाए और निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों से कोई समझौता न हो। लोगों को उम्मीद है कि मानसून के दौरान सामने आई समस्याओं से सबक लेते हुए संबंधित एजेंसियां तेजी से काम करेंगी और शहर को लंबे समय से चली आ रही इन परेशानियों से राहत मिलेगी।

जल निकासी व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

विशेषज्ञों का मानना है कि मोहाली की वर्तमान चुनौतियों का एक बड़ा कारण जल निकासी व्यवस्था पर बढ़ता दबाव भी है। शहर का तेजी से विस्तार हुआ है और कई नए आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र विकसित हुए हैं। इसके कारण वर्षा जल के प्राकृतिक प्रवाह में बदलाव आया है। यदि नई परियोजनाओं के साथ पर्याप्त ड्रेनेज नेटवर्क विकसित नहीं किया जाता तो बारिश के दौरान जलभराव की समस्या बढ़ना स्वाभाविक है। शहरी नियोजन से जुड़े जानकारों का कहना है कि केवल सड़क निर्माण पर्याप्त नहीं है। सड़क, नाली, सीवरेज और वर्षा जल निकासी प्रणाली को एकीकृत दृष्टिकोण से विकसित करना आवश्यक है।

मानसून से पहले ड्रेनेज व्यवस्था की जांच आवश्यक

नगर निगम और अन्य संबंधित एजेंसियों का कहना है कि कई परियोजनाएं चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा रही हैं। कुछ स्थानों पर सीवरेज और पाइपलाइन कार्य पूरा होने के बाद ही सड़क का अंतिम निर्माण किया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार बारिश के कारण कई बार निर्माण कार्य की गति प्रभावित होती है। उनका कहना है कि प्राथमिकता उन हिस्सों को दी जा रही है जहां यातायात का दबाव सबसे अधिक है। शहरी नियोजन विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सड़क परियोजना में निर्माण और जल निकासी दोनों कार्य साथ-साथ पूरे होने चाहिए। यदि सड़क बन जाए लेकिन नालियां अधूरी रह जाएं तो पहली ही बारिश में सड़क क्षतिग्रस्त होने लगती है। विशेषज्ञों के अनुसार परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी, गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री और मानसून से पहले ड्रेनेज व्यवस्था की जांच आवश्यक है। अन्यथा हर वर्ष यही स्थिति दोहराई जाती रहेगी।

व्यापार पर भी असर

सड़क निर्माण और जलभराव का असर आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी पड़ा है। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक खराब सड़क और जाम के कारण बाजार आने से बचते हैं। कई जगह निर्माण सामग्री, कीचड़ और धूल के कारण दुकानों तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। व्यापारियों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य तय समय में पूरा होता तो उन्हें इतनी आर्थिक क्षति नहीं उठानी पड़ती। फेज-9, बलौंगी और आसपास के इलाकों के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायतें दी हैं, लेकिन काम की गति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। बारिश के दौरान घरों के बाहर पानी जमा होने, कीचड़ बनने और मच्छरों की समस्या भी बढ़ जाती है। कई कॉलोनियों में सीवरेज का पानी भी सड़कों पर आने की शिकायतें सामने आई हैं।

दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क किनारे कई नालियां बिना ढक्कन के खुली हुई हैं। रात के समय या बारिश के दौरान इनमें पानी भर जाने से इनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। इससे वाहन चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। बीते महीनों में कई वाहन इन नालियों में फंसने या गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। स्थानीय निवासी लंबे समय से इन नालियों को ढकने और सुरक्षा बैरिकेड लगाने की मांग कर रहे हैं। निर्माण कार्य के कारण कई स्थानों पर सड़क का केवल एक हिस्सा ही यातायात के लिए उपलब्ध है। परिणामस्वरूप दोनों दिशाओं का ट्रैफिक एक ही लेन से गुजरता है। सुबह और शाम कार्यालय समय में लंबा जाम लगना आम बात हो गई है। रोजाना मोहाली, चंडीगढ़ और खरड़ के बीच सफर करने वाले लोगों का कहना है कि सामान्य दिनों में 20 मिनट का सफर कई बार एक घंटे तक पहुंच जाता है। बारिश होने पर स्थिति और खराब हो जाती है।

देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन कल होगी रवाना, अंबाला में यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में उत्साह

हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला भारत दुनिया का चौथा देश, हरियाणा की धरती पर पीएम मोदी करेंगे रवाना, यह परियोजना भारतीय रेलवे को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था की दिशा में नई पहचान देगी

अंकुर कपूर | अंबाला
समर न्यूज

देश की पहली पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार हाइड्रोजन ट्रेन 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए जाने की तैयारी है। भारतीय रेलवे की इस ऐतिहासिक उपलब्धि को लेकर अंबाला में यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के बीच उत्साह का माहौल है। लोगों का मानना है कि यह परियोजना भारतीय रेलवे को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था की दिशा में नई पहचान देगी।

भारत इस उपलब्धि के साथ हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत तैयार की गई इस ट्रेन का पहला संचालन हरियाणा के जींद-सोनीपत रेलखंड पर किया जाएगा।

रेलवे का उद्देश्य पहले इस रूट पर सफल संचालन सुनिश्चित करना है, जिसके बाद इसे अन्य रेल मार्गों पर भी चलाने की योजना बनाई जाएगी। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन (एनआरएमयू) अंबाला मंडल के

सचिव ठाकुर सिंह ने इसे पूरे देश, विशेषकर हरियाणा के लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन हरियाणा से शुरू होना ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनका कहना है कि इस तकनीक से ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण में कमी आएगी और भारतीय रेलवे को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने इस पहल के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया।

वहीं, ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों ने भी इस पहल का स्वागत किया। यात्रियों का कहना है कि देश में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू होना गर्व की बात है। उनका मानना है कि इससे आधुनिक, स्वच्छ और बेहतर रेल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।

यात्रियों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल रहा है।

नहीं रुक रहीं प्रदेश में अग्निकांड की घटनाएं, प्रशासन की बेबसी बनी नागरिकों के नुकसान का बड़ा कारण

गुरुग्राम की लाइफ लॉन्ग फैक्ट्री में भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर राख, घटना के समय फैक्ट्री में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था

अनुज पांचाल | गुरुग्राम
समर न्यूज

गुरुग्राम के केएमपी हाईवे से सटे पटौदी रोड स्थित झुंड सराय इलाके में देर रात एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग स्पोर्ट्स और मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली लाइफ लॉन्ग कंपनी में लगी, जिसने देखते ही देखते फैक्ट्री के दो ब्लॉकों को अपनी चपेट में ले लिया।

हादसे में करोड़ों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना के समय फैक्ट्री में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल विभाग को रात करीब 10:30 बजे आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही गुरुग्राम, मानेसर और आसपास के क्षेत्रों से दमकल विभाग की डेढ़ दर्जन से अधिक गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।

कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और उसे अन्य हिस्सों में फैलने से रोका। फायर अधिकारियों के अनुसार, करीब चार एकड़ में फैली इस फैक्ट्री में स्पोर्ट्स और मेडिकल उपकरणों का निर्माण किया जाता है। आग की तीव्रता को देखते हुए अतिरिक्त दमकल वाहनों की सहायता लेनी पड़ी। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक आग से कंपनी को करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फायर विभाग और संबंधित एजेंसियां घटना की जांच में जुटी हैं।

मानेसर फायर ऑफिसर नरेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे में किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। आग लगने के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

गुरुग्राम के किंगडम ऑफ ड्रीम्स में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने पाया काबू

गुरुग्राम की पहचान रहे किंगडम ऑफ ड्रीम्स में बुधवार दोपहर भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद दमकल विभाग की पांच गाड़ियां और बचाव दल मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब 1:30 बजे फायर कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना मिली थी।

इसके बाद तत्काल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना की गईं। दमकल कर्मियों की मेहनत से आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के मुताबिक, किंगडम ऑफ ड्रीम्स पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है और परिसर के अंदर कबाड़ व पुराना सामान रखा हुआ था, जिससे आग तेजी से फैल गई। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। पुलिस और फायर विभाग की टीमें आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हैं। आग पूरी तरह बुझने के बाद ही नुकसान और घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

रेवाड़ी में पेड़ से जा टकराई निजी बस पूर्व सैनिक की मौत; 11 यात्री घायल

- करीब 30 यात्रियों को लेकर कोसली जा रही बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से भिड़ी, घायलों का अस्पताल में उपचार जारी

समर न्यूज। रेवाड़ी

हरियाणा के रेवाड़ी जिले में बुधवार सुबह एक निजी बस के पेड़ से टकरा जाने से एक पूर्व सैनिक की मौत हो गई, जबकि 11 यात्री घायल हो गए। हादसे के समय बस में लगभग 30 यात्री सवार थे और वह रेवाड़ी से कोसली की ओर जा रही थी।

जानकारी के अनुसार, बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा भिड़ी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, राहगीर और पुलिस मौके पर पहुंचे।

घायलों को तुरंत एंबुलेंस की मदद से कोसली के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार अधिकांश घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मृतक की पहचान पूर्व सैनिक दीपचंद के रूप में हुई है।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में बस के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है, हालांकि तकनीकी खराबी, चालक की लापरवाही अथवा अन्य संभावित कारणों की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

सुरक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल: इस हादसे के बाद निजी बसों की सुरक्षा, नियमित फिटनेस जांच और सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से दुर्घटना के वास्तविक कारणों की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रशासन ने घायलों के समुचित उपचार और जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है।

राई फ्लाईओवर के पास दर्दनाक सड़क हादसा कैंटर चालक की मौत, पिकअप चालक गंभीर

समर न्यूज | सोनीपत (राई): राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर राई फ्लाईओवर के समीप बुधवार को हुए सड़क हादसे में कैंटर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिकअप वैन का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना पानीपत से दिल्ली जाने वाली लेन पर हुई। पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, दिल्ली के आरके पुरम सेक्टर-6 निवासी ओमप्रकाश अपने आइशर कैंटर में पानीपत से दरी और कंबल लेकर दिल्ली लौट रहे थे। इसी दौरान राई फ्लाईओवर के पास आगे चल रही पिकअप वैन के चालक ने कथित रूप से अचानक ब्रेक लगा दिए। अचानक ब्रेक लगने से पीछे आ रहा कैंटर संतुलन खो बैठा और सीधे पिकअप से जा टकराया।

टक्कर इतनी भीषण थी कि कैंटर चालक ओमप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना एक राहगीर ने मृतक के मोबाइल फोन से उनके बेटे कुनाल को दी। कुनाल ने अपनी शिकायत में पिकअप चालक की लापरवाही को हादसे का कारण बताते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दुर्घटना में पिकअप चालक रामलोचन यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया।

राई थाना पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

फरीदाबाद में लटकते बिजली के तार बने खतरा, बारिश और आंधी में बढ़ रहा हादसों का डर

समर न्यूज | फरीदाबाद

शहर के कई इलाकों में बिजली निगम की लापरवाही लोगों की सुरक्षा पर भारी पड़ रही है। विभिन्न स्थानों पर बिजली के तार खुलेआम लटके हुए हैं, जबकि कई जगह ये पेड़ों की टहनियों के बीच से गुजर रहे हैं।

बारिश और तेज आंधी के दौरान ऐसे हालात बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब तक इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा सके हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति पांच नंबर डी-ब्लॉक और प्याली चौक स्थित पार्कों की है, जहां बिजली के तार काफी नीचे लटक रहे हैं।

इन पार्कों में रोजाना बड़ी संख्या में लोग सुबह-शाम सैर और व्यायाम के लिए पहुंचते हैं, जिससे किसी भी समय दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। इसी तरह नागरिक अस्पताल

के मुख्य प्रवेश द्वार पर भी बिजली की तारें लटकती दिखाई दे रही हैं। अस्पताल परिसर में कई स्थानों पर बिजली की लाइनें पेड़ों की टहनियों के बीच से गुजर रही हैं। बरसात के मौसम में इन तारों के संपर्क में आने से करंट फैलने और गंभीर हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन बिजली निगम के अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। हैरानी की बात यह है कि संबंधित एसडीओ, जेई और लाइनमैन के संज्ञान में मामला होने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है।

वहीं, बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता जितेंद्र ढुल का कहना है कि विभाग की ओर से समय-समय पर पेड़ों की टहनियों की छंटाई कराई जाती है। हालांकि, शहर के कई क्षेत्रों में अब भी लटकते तार लोगों के लिए खतरे का कारण बने हुए हैं।

हरियाणा में मतदाता सूची संशोधन कार्यक्रम बदला

समर न्यूज | चंडीगढ़

हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सारिणी में भारत निर्वाचन आयोग ने बदलाव किया है। आयोग ने संशोधित कार्यक्रम जारी करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) हरियाणा को नए शेड्यूल के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, अब मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) 31 जुलाई 2026 को प्रकाशित किया जाएगा। वहीं, सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी।

आयोग ने निर्देश दिए हैं कि संशोधित कार्यक्रम की जानकारी राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों तक तत्काल पहुंचाई जाए। साथ ही विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए नए कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि मतदाताओं को समय पर इसकी जानकारी मिल सके। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी संशोधित कार्यक्रम की लिखित सूचना देने के निर्देश दिए हैं, जिससे वे भी मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

निर्वाचन आयोग का उद्देश्य संशोधित कार्यक्रम के माध्यम से मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि आगामी चुनावों के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में अंबाला में किसानों की बाइक रैली, डीसी को सौंपा ज्ञापन

अंकुर कपूर | अंबाला
समर न्यूज

भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में मंगलवार को अंबाला में विभिन्न किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने बाइक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि प्रस्तावित ट्रेड डील देश के किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के हितों के विपरीत है, इसलिए इसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।

बड़ी संख्या में किसान बाइक रैली के रूप में शहर की सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप था कि यदि यह ट्रेड डील लागू होती है तो विदेशी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खुल जाएगा, जिससे देश के कृषि क्षेत्र को बड़ा नुकसान होगा।

उनका कहना है कि इससे किसानों की आय प्रभावित होगी और छोटे व्यापारियों के सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर किसानों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र सरकार से प्रस्तावित समझौते को वापस लेने की मांग की। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

किसान नेताओं ने बताया कि 21 जुलाई को दिल्ली स्थित किसान घाट पर देशभर के किसान एकत्रित होंगे।

बारिश से फिर लौटी उमस भरी गर्मी, अंबाला में लोग बेहाल

अंकुर कपूर | अंबाला
समर न्यूज

लगातार हुई बारिश से मिली राहत अब खत्म होती नजर आ रही है। अंबाला में एक बार फिर उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी और उमस का असर इतना बढ़ गया है कि लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं।

तेज धूप और चिपचिपी गर्मी से बचने के लिए लोग मुंह और सिर को कपड़े से ढककर निकल रहे हैं, जबकि बाजारों में ठंडे पेय और जूस की दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी है। जून और शुरुआती जुलाई में लगातार हुई बारिश के कारण मौसम सुहावना बना हुआ था, लेकिन अब बारिश थमने के साथ ही उमस ने फिर से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। बाजारों में भी लोगों की आवाजाही पहले के मुकाबले कम देखने को मिल रही है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान मौसम काफी आरामदायक था, लेकिन अब उमस के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। फिलहाल केवल जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। लोगों का मानना है कि उमस से राहत केवल अच्छी बारिश से ही मिल सकती है, लेकिन बारिश इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि बाढ़ जैसे हालात बन जाएं।

करनाल क्रिकेटर हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई 12 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को हिरासत में लिया

राकेश कुमार शर्मा | करनाल
समर न्यूज

करनाल के धौलगढ़ गांव में 16 वर्षीय छात्र और उभरते क्रिकेट खिलाड़ी प्रतीक की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात के 10 से 12 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस ने परिजनों की शिकायत, सीसीटीवी फुटेज और प्रारंभिक जांच के आधार पर यह कार्रवाई की। हिरासत में लिए गए तीनों युवक करनाल के जुंडला कस्बे के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनसे गहन पूछताछ की जा रही है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी

कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच के अनुसार, प्रतीक उचाना गांव स्थित हनुमान मंदिर से प्रसाद लेकर बाइक से अपने घर लौट रहा था।

इसी दौरान धौलगढ़ गांव के बाहरी क्षेत्र में खेतों के पास पहले से घात लगाए बैठे नकाबपोश युवकों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से उस पर ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि हत्या के पीछे स्कूल में किसी लड़की को लेकर हुआ पुराना विवाद कारण हो सकता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है और पूछताछ पूरी होने के बाद ही हत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाएगा।

प्रतीक की हत्या के बाद धौलगढ़ गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि घटना के बाद पूरे गांव में किसी घर में चूल्हा तक नहीं जला। प्रतीक अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और उसकी दो बहनें हैं।

जांच | सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को बजट आवंटन के आदेश

शिक्षकों-कर्मियों की मेडिकल प्रतिपूर्ति के लिए 46.20 करोड़ जारी

समर न्यूज | चंडीगढ़

हरियाणा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के दौरान शिक्षकों और कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल री-इम्बर्समेंट) दावों के भुगतान के लिए 46 करोड़ 20 लाख रुपये का बजट जारी कर दिया है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को बजट आवंटन के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के प्रशासनिक स्टाफ के चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद के लिए 10 लाख रुपये तथा संबंधित जिले के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के

शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक जिले को कुल 2.10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आवंटित राशि का उपयोग केवल चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में ही किया जाएगा।

जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्त दावों का नियमानुसार परीक्षण कर स्वीकृति देंगे और निर्धारित प्रक्रिया के तहत भुगतान सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी भुगतान वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कोषागार के माध्यम से किए जाएंगे।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्वीकृत बजट से अधिक राशि खर्च नहीं की जा सकती। यदि किसी स्तर पर वित्तीय अनियमितता या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।

इन जिलों को मिला 2.10 करोड़ रुपये का आवंटन: अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, जींद, झज्जर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, नूंह (मेवात), महेंद्रगढ़ (नारनौल), पंचकूला, पलवल, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर।

हरियाणा पुलिस का फर्जी अधिकारी बन मेडिकल संचालक से की वसूली

समर न्यूज | भिवाड़ी

भिवाड़ी फेज थर्ड थाना पुलिस ने खुद को हरियाणा पुलिस की क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर मेडिकल स्टोर संचालक से रंगदारी वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पीड़ित से 50 हजार रुपये की दूसरी किस्त लेने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने पहले से बिछाए जाल में उन्हें दबोच लिया।

तीन अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि हरियाणा के नूंह जिले के सुनारी गांव निवासी अजरूदीन सांथलका क्षेत्र में भारत फार्मेसी नाम से मेडिकल स्टोर संचालित करते हैं।

विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नयना देवी में गुप्त नवरात्र का शुभारंभ, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी

सुभाष | बिलासपुर
समर न्यूज

विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नयना देवी में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्रि बुधवार से श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक उत्साह के साथ आरंभ हो गए। प्रातःकाल मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण और विशेष आरती के साथ माता रानी के गुप्त नवरात्रों का शुभारंभ हुआ।

सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचे। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और मंगलकामना की। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और दर्शन की विशेष व्यवस्था की। भक्तों को सुव्यवस्थित कतारों के माध्यम से माता के दर्शन कराए गए, जिससे दर्शन व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रही।

पुजारी मुकेश शर्मा ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार वर्ष में चार नवरात्रि मनाए जाते हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि के साथ दो गुप्त नवरात्रि भी शामिल हैं। गुप्त नवरात्रि को शक्ति साधना, विशेष पूजा-अर्चना, हवन और यज्ञ के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी कारण इन नौ दिनों में दूर-दराज से श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचकर विशेष अनुष्ठान कराते हैं और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुप्त नवरात्रि शक्ति साधना का विशेष पर्व है। इन दिनों माता की पूजा, हवन और यज्ञ का विशेष महत्व होता है। जो श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से माता की आराधना करते हैं, उन पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है।

उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्य के लिए श्री नयना देवी के एसडीएम धर्मपाल चौधरी को मिला इंडियन एक्सीलेंस अवॉर्ड-2026

संजू | शिमला
समर न्यूज

श्री नैना देवी जी के एसडीएम धर्मपाल चौधरी को उनके उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्य, जनसेवा के प्रति समर्पण और सामाजिक सरोकारों में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंडियन एक्सीलेंस अवॉर्ड-2026 से सम्मानित किया गया।

यह सम्मान लाडली फाउंडेशन, हिमाचल रेनबो स्टार क्लब, गोविंद सागर एडवेंचर एंड वॉटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन तथा सर्वधर्म समभाव राष्ट्रीय मंच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। इस अवसर पर उन्हें हिमाचली टोपी और शॉल ओढ़ाकर भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लाडली फाउंडेशन के राज्य अध्यक्ष शालु अख़्तर, हिमाचल रेनबो स्टार क्लब की पदाधिकारी नर्बदा शर्मा और दीक्षा शर्मा, हिमाचल वाटर स्पोर्ट्स के राज्य महासचिव के. इशान अख़्तर, सर्वधर्म समभाव राष्ट्रीय मंच के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर श्यामलाल पंवार और क्लब के पदाधिकारी पवन कुमार, नंदलाल, वंदना ठाकुर और मोनिका नरवाल उपस्थित रहे।

सभी ने एसडीएम धर्मपाल चौधरी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने प्रशासन को जनहित से जोड़ने का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है।वक्ताओं ने बताया कि धर्मपाल चौधरी ने श्री नैना देवी जी उपमंडल में सामाजिक

और बुनियादी ढांचे के स्तर पर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। मंदिर के चेयरमैन के रूप में उन्होंने नागरिक-केंद्रित शासन की ऐसी संवेदनशील और प्रभावी व्यवस्था विकसित की, जिससे मंदिर की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। साथ ही लंगर सेवाओं को बेहतर बनाया गया, श्रद्धालुओं और विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया गया तथा परिसर में विश्व-स्तरीय साफ-सफाई और सुगम पहुंच सुनिश्चित की गई।उनकी पहल पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित की गई, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को नई दिशा मिली।

सबसे खास बात यह रही कि उनकी नई सोच के कारण मंदिर के इतिहास में पहली बार ऐतिहासिक 40वां ट्रस्ट स्थापना दिवस भव्य रूप से मनाया गया। इस आयोजन में 3,000 से अधिक छात्रों ने खेलकूद, साइंस क्विज़ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को पहचान और मंच मिला। धर्मपाल चौधरी के नेतृत्व में विरासत संरक्षण और आधुनिक तकनीक का भी सुंदर समन्वय देखने को मिला। 850 वर्ष पुराने हवन कुंड का जीर्णोद्धार कराया गया और भीड़ प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की व्यवस्था लागू की गई। आपदा प्रबंधन के दौरान उनकी तत्परता और कुशलता की भी व्यापक सराहना हुई।

राज्यपाल द्वारा उन्हें पहले भी 'बेस्ट ईआरओ' के रूप में सम्मानित किया जा चुका है।इस मौके पर एसडीएम धर्मपाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश के विकास और जनहित तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता की सेवा ही प्रशासन का असली उद्देश्य है और वे आगे भी इसी भावना के साथ कार्य करते रहेंगे।

हिमाचल में कैबिनेट विस्तार टला; राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक भी हुई स्थगित

केसी वेणुगोपाल के धर्मशाला दौरे पर रोक, राजनीतिक नियुक्तियों व मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसले में होगी और देरी

समर न्यूज | शिमला

पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी खींचतान का असर अब हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर भी दिखाई देने लगा है। कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की धर्मशाला में प्रस्तावित बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई है।

इसके साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का हिमाचल दौरा भी टल गया है। इस घटनाक्रम के चलते राज्य मंत्रिमंडल के लंबे समय से लंबित विस्तार, संभावित फेरबदल और विभिन्न राजनीतिक नियुक्तियों पर फैसला भी फिलहाल आगे बढ़ गया है।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेतृत्व का पूरा ध्यान इस समय पंजाब कांग्रेस में चल रहे संगठनात्मक विवाद को सुलझाने पर केंद्रित है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थक नेताओं तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच मतभेद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। हाल के दिनों में वरिष्ठ नेताओं की बैठकें हुई हैं, लेकिन विवाद का अंतिम समाधान नहीं निकल सका। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व की व्यस्तता के कारण हिमाचल से जुड़े संगठनात्मक कार्यक्रमों को फिलहाल टाल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्रिमंडल में अभी एक मंत्री पद रिक्त है। पिछले कई महीनों से इस पद को भरने और कुछ राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा चल रही थी। माना जा रहा था कि धर्मशाला में होने वाली पीएसी बैठक के दौरान इन विषयों पर अंतिम सहमति बन सकती है, लेकिन बैठक स्थगित होने से इन फैसलों में और विलंब तय है।

संगठनात्मक फैसलों पर ब्रेक

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अब पीएसी की नई तिथि शीर्ष नेतृत्व की उपलब्धता के अनुसार तय की जाएगी। बैठक होने के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार, संभावित फेरबदल, बोर्ड-निगमों में नियुक्तियां और संगठन से जुड़े अन्य लंबित मामलों पर आगे बढ़ने की संभावना है। फिलहाल सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर फैसलों का इंतजार जारी है।

पंजाब विवाद सुलझने का इंतजार

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब कांग्रेस में चल रहा विवाद शांत होने के बाद ही केंद्रीय नेतृत्व हिमाचल के लंबित मामलों पर पूरा ध्यान दे सकेगा। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक तौर पर दोनों राज्यों के मामलों को अलग बता रहे हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में शीर्ष नेतृत्व की प्राथमिकताओं का असर हिमाचल के राजनीतिक कार्यक्रमों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

देउरी स्कूल भवन मामले में हाई कोर्ट सख्त सरकार और शिक्षा विभाग से मांगा जवाब

समर न्यूज | मंडी

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र की देउरी पंचायत स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के नए भवन को लेकर मामला अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गया है।

भवन तैयार होने के बावजूद विद्यार्थियों को अब तक नए परिसर में स्थानांतरित नहीं किए जाने के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई निर्धारित की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सचिव शिक्षा, निदेशक उच्च शिक्षा, उपायुक्त मंडी, उपनिदेशक उच्च शिक्षा मंडी तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देउरी के प्रधानाचार्य को नोटिस जारी किए हैं।

अदालत ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई से पहले अपना पक्ष स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता उदयनंद शर्मा ने अदालत को बताया कि वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा में देउरी स्कूल का पुराना भवन क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद से छात्र-छात्राएं किराए के भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि नया स्कूल भवन पूरी तरह तैयार है, लेकिन अब तक उसे विद्यार्थियों के लिए शुरू नहीं किया गया है।याचिका में यह भी कहा गया है कि जिस किराए के भवन में वर्तमान में कक्षाएं संचालित हो रही हैं, वह पुराना होने के साथ-साथ बरसात के मौसम में सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरी तरह उपयुक्त नहीं है। ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण को लेकर अभिभावकों में लगातार चिंता बनी हुई है।

अदालत ने इस बात को गंभीरता से लिया कि भवन तैयार होने के बावजूद उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। न्यायालय ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि विद्यार्थियों को नए भवन में स्थानांतरित करने में देरी किस कारण से हो रही है। साथ ही सभी अधिकारियों को 22 जुलाई से पहले विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

18 जुलाई से हिमाचल में फिर सक्रिय होगा मानसून

संजू | शिमला
समर न्यूज

:हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़े मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 18 जुलाई से प्रदेश में मानसून दोबारा रफ्तार पकड़ेगा और इसके साथ ही कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। विभाग ने 20 और 21 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 18 और 19 जुलाई को कई क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट रहेगा।

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि 12 जुलाई के बाद प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कमजोर हो गई थीं, जिससे बारिश में कमी आई और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि अब मौसम प्रणाली फिर से सक्रिय हो रही है और 18 जुलाई से बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। यह सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रह सकता है।विभाग के अनुसार कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में भारी बारिश का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सोलन, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भी अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। लगातार होने वाली वर्षा के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, मलबा गिरने और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।

मौसम विभाग ने लोगों और पर्यटकों के लिए विशेष एडवाइजरी भी जारी की है। 18 से 23 जुलाई के बीच नदी-नालों और अन्य जल स्रोतों से दूरी बनाए रखने, संवेदनशील इलाकों की यात्रा से बचने तथा मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है।

बारिश में कमी के कारण पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का असर बढ़ गया है। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। 17 जुलाई तक तापमान में बढ़ोतरी बनी रह सकती है।

15 सितंबर तक राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग बंद, ट्रेकिंग रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं

राहुल | धर्मशाला
समर न्यूज

मानसून के दौरान पर्यटकों और ट्रैकर्स की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कांगड़ा जिला प्रशासन ने एडवेंचर स्पोर्ट्स और ट्रेकिंग गतिविधियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश लागू कर दिए हैं। भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक बढ़ते जलस्तर जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों को देखते हुए कई साहसिक गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ रेस्क्यू अभियान का पूरा खर्च भी संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा।

जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि 15 जुलाई से 15 सितंबर तक जिले में रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी एडवेंचर गतिविधियों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। यह निर्णय मानसून के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।इसके अलावा धौलाधार पर्वत श्रृंखला के 10 चिन्हित ट्रेकिंग मार्गों पर 15 अक्टूबर तक बिना पंजीकरण किसी भी ट्रैकर को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

केंद्र की योजनाओं से कुटलैहड़ को मिली विकास की रफ्तार, भाजपा की जीत पक्की: सूरम सिंह

कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में भाजपा, चार्जशीट और जनसंपर्क अभियान के लिए दो समितियां गठित

राकेश | ऊना
समर न्यूज

जिला भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष सूरम सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, विशेषकर कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के विकास में केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान प्रदेश सरकार केवल पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं का श्रेय लेने का प्रयास कर रही है, जबकि अधिकांश विकास कार्य भाजपा शासनकाल में स्वीकृत योजनाओं के आधार पर आगे बढ़े हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा कुटलैहड़ सीट पर बड़ी जीत दर्ज करेगी और पूर्व विधायक दविंदर कुमार भुट्टो करीब 15 हजार मतों के अंतर से विजयी होंगे।

सूरम सिंह ने कहा कि पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता दविंदर कुमार भुट्टो ने अपने कार्यकाल के दौरान केंद्र से कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 31 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाएं स्वीकृत करवाई थीं। इन योजनाओं का लाभ आज भी क्षेत्र की जनता को मिल रहा है।

संजू | शिमला
समर न्यूज

हिमाचल प्रदेश भाजपा ने राज्य की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने सरकार के खिलाफ तथ्यों और मुद्दों को संकलित करने के लिए एक चार्जशीट समिति तथा प्रदेशभर में जनसंपर्क और जन आंदोलन चलाने के उद्देश्य से दूसरी समिति का गठन किया है। चार्जशीट समिति में 13 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर, राज्यसभा सांसद प्रो. सिकंदर कुमार और हर्ष महाजन सहित कई विधायक एवं संगठन पदाधिकारी शामिल हैं। समिति का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जुड़े विभिन्न मुद्दों, वादों और नीतिगत फैसलों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करना होगा। दूसरी ओर, जन आंदोलन समिति में 14 नेताओं को शामिल किया गया है।

इस समिति में डॉ. राजीव बिंदल, जयराम ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप, डॉ. राजीव भारद्वाज, लोकसभा सांसद कंगना रणौत, विपिन सिंह परमार, पवन काजल, विनोद कुमार, बिहारी लाल शर्मा, राकेश जम्वाल, गोविंद सिंह ठाकुर, डॉ. राजीव सैजल, रश्मिधर सूद और डीएस ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई है।

भाजपा का कहना है कि दोनों समितियां समन्वित रूप से काम करेंगी। चार्जशीट समिति सरकार की नीतियों और कार्यों का आकलन कर दस्तावेज तैयार करेगी, जबकि जन आंदोलन समिति प्रदेश के विभिन्न जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंचकर पार्टी के अभियान को गति देगी।

शिमला के लोअर बाजार सब्जी मंडी मार्ग की शीघ्र बहाली की मांग को लेकर कर्ण नंदा ने नगर निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

समर न्यूज | शिमला

भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने आज नगर निगम शिमला के आयुक्त श्री सचिन कंवल से उनके कार्यालय में भेंट कर लोअर बाजार सब्जी मंडी को जाने वाले भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्ग की शीघ्र मरम्मत एवं वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा।

कर्ण नंदा ने आयुक्त को बताया कि हाल ही में हुई भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण कार्ट रोड से लोअर बाजार सब्जी मंडी को जोड़ने वाला मार्ग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। किसानों, आढ़तियों, व्यापारियों तथा आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियों एवं अन्य कृषि उत्पादों को सीधे मंडी तक नहीं पहुंचाया जा पा रहा है, जिससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है और इसका प्रभाव आम जनता तक बढ़ती सब्जियों की कीमतों के रूप में पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में यदि इस सड़क की शीघ्र मरम्मत नहीं की गई तो राजधानी शिमला की प्रमुख सब्जी मंडी में आपूर्ति प्रभावित होगी, जिससे आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने आग्रह किया कि इस कार्य को जल्द पूरा किया जाए।

ज्ञापन में भाजपा की ओर से मांग की गई कि क्षतिग्रस्त सड़क की युद्धस्तर पर तत्काल मरम्मत करवाई जाए, सड़क पूरी तरह बहाल होने तक किसानों और व्यापारियों के लिए सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराया जाए, कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए तथा नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन के समन्वय से कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। भविष्य में ऐसे संवेदनशील स्थलों पर रिटेनिंग वॉल, बेहतर ड्रेनेज और ढलान संरक्षण जैसे स्थायी सुरक्षा कार्य भी किए जाएं।

नगर निगम आयुक्त सचिन कंवल ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले पर विस्तार से चर्चा की तथा आश्वस्त किया कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और मार्ग को जल्द से जल्द सुचारु बनाने का प्रयास किया जाएगा।

आह्वान राज्यपाल ने कहा- औषधीय पौधों के वैज्ञानिक उपयोग से हिमाचल में हरित उद्यम राजधानी बनने की क्षमता

राज्यपाल ने शिमला जिले के मेधावियों को किया सम्मानित

समर न्यूज | हिमाचल

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि प्रतिष्ठित सेवाओं में चयनित होने का लक्ष्य निर्धारित करना सराहनीय है, लेकिन सफलता केवल एक करियर की उपलब्धि तक सीमित नहीं है। उन्होंने युवाओं को नवाचार, उद्यमिता और वैज्ञानिक अनुसंधान, विशेषकर औषधीय पौधों एवं प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में उपलब्ध विविध अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में एक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने शिमला जिले के 35 से अधिक विद्यालयों के लगभग 600 मेधावियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। गुप्ता ने कहा कि न्यूज़ीलैंड ने वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप मनुका पौधे का बाजार विकसित किया है, दक्षिण कोरिया ने जिनसेंग को एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन में परिवर्तित किया है, जबकि लैवेंडर की खेती से जम्मू-कश्मीर के लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन आया है।

हिमाचल प्रदेश में औषधीय जड़ी-बूटियों, सुगंधित पौधों तथा अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों का समृद्ध भंडार है। वैज्ञानिक खेती, मूल्य संवर्धन और नवाचार के माध्यम से इस भंडार का सर्वोत्तम उपयोग कर हजारों युवाओं के लिए सतत् आजीविका के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हमारे युवा नवाचार को प्रदेश के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के साथ जोड़ें, तो हिमाचल प्रदेश भारत के बागवानी केन्द्र के साथ-साथ हरित उद्यमिता की राजधानी के रूप में भी उभर सकता है।

शिक्षा के महत्व को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं है बल्कि यह चरित्र निर्माण, नवाचार को बढ़ावा देने और युवाओं को समाज तथा राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देने के लिए सक्षम बनाने का माध्यम है। उन्होंने मेधावियों को देश के स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, प्रगतिशील और नैतिक मूल्य आधारित भारत का प्रतिनिधि बताया। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों की उपलब्धियां उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और ज्ञान प्राप्त करने की अटूट जिज्ञासा का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। उन्होंने विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ-साथ सह-पाठ्यक्रम एवं अन्य गतिविधियों में उनकी उत्कृष्टता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि वास्तविक शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं होती।

नशे की बुराई के प्रति सचेत रहने का आह्वान: राज्यपाल ने विद्यार्थियों से नशे की बुराई के प्रति सचेत रहने का आह्वान करते हुए कहा कि मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाज के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने तथा अपने मित्रों और सहपाठियों को भी इसके प्रति इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यापीठ संस्थान द्वारा शुरू की गई 'कलम ऑफ हिमाचल' पहल का भी शुभारंभ किया। इससे पूर्व आयोजनकर्ता समाचार पत्र समूह के राज्य ब्यूरो प्रमुख राजेश मंढोतरा ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।

चढ़ावा चोरी पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जताई चिंता, बोले- सख्त कार्रवाई हो

राहुल चावला | पालमपुर
समर न्यूज

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

उन्होंने कहा कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। रोहित ठाकुर ने कहा कि अयोध्या देश की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में यदि मंदिर के चढ़ावे या उसके प्रबंधन से जुड़ी किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो इससे श्रद्धालुओं का विश्वास प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि सरकार को पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराकर सच्चाई जनता के सामने लानी चाहिए और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थानों की विश्वसनीयता बनाए रखना सभी सरकारों और प्रबंधन समितियों की जिम्मेदारी है। श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के साथ मंदिरों में दान देते हैं, इसलिए उस धन का उपयोग पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। यदि कहीं भी अनियमितता होती है तो उसे गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच इसलिए उठा रही है ताकि धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। उनका कहना था कि किसी भी धर्मस्थल की गरिमा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष व्यवस्था और प्रभावी निगरानी तंत्र आवश्यक है।

प्रदेश के मंदिरों में व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि हिमाचल सहित देश के सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधन को इस घटना से सीख लेते हुए वित्तीय लेनदेन और दान प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और नियमित ऑडिट जैसी व्यवस्थाएं अपनाकर श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित चंडीगढ़ दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट, उपायुक्त ने की तैयारियों की समीक्षा

मोहाली हाई अलर्ट पर, पांच जिलों और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात, 1500 जवानों का सुरक्षा घेरा

शगुन कश्यप | चंडीगढ़
समर न्यूज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई, 2026 को प्रस्तावित चंडीगढ़ दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में उपायुक्त, यू.टी. चंडीगढ़, निशांत कुमार यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में सुरक्षा, प्रोटोकॉल, यातायात प्रबंधन, कार्यक्रम स्थल प्रबंधन, पार्किंग, जनसुविधाओं, आपातकालीन सेवाओं और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने-अपने जिम्मे सौंपे गए कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें, ताकि कार्यक्रम का संचालन सुचारु और त्रुटिरहित हो सके। उपायुक्त ने कार्यक्रम स्थल पर पेयजल, सार्वजनिक पार्किंग, शौचालय और चिकित्सा सहायता की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बरसात की संभावना को देखते हुए जल निकासी, जलभराव रहित परिसर और लोगों के लिए सुरक्षित व सूखे पैदल मार्ग तैयार रखने के भी निर्देश दिए।

कार्यक्रम स्थल पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ और वीवीआईपी मूवमेंट मार्गों पर स्थल प्रभारी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और सेक्टर प्रभारियों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ये अधिकारी मंच प्रबंधन, बैठक व्यवस्था, प्रोटोकॉल, पार्किंग, भीड़ प्रबंधन और कानून-व्यवस्था की निगरानी करेंगे। उपायुक्त ने बताया कि 16 जुलाई को सभी तैयारियों का आकलन करने और एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए व्यापक ड्राई रन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को ड्राई रन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और किसी भी कमी को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए।

बैठक में चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ पुलिस, इंजीनियरिंग विभाग, परिवहन विभाग, नगर निगम, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुल्लांपुर और एयरपोर्ट रूट पर विशेष निगरानी : ट्रैफिक एडवाइजरी जारी होगी, क्विक रिस्पॉन्स टीमों की तैनाती

मोहाली। मोदी के दौरे को लेकर मोहाली पुलिस पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पांच जिलों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स सहित करीब 1500 जवानों की तैनाती की गई है। मुल्लांपुर रूट के लिए शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जाने वाले मार्ग और जिले के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार को एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में जिले के सभी एसपी, डीएसपी, एसएचओ के अलावा सुरक्षा व्यवस्था में शामिल पड़ोसी जिलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़े सभी सुरक्षा पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की गई और संबंधित विभागों से तैयारियों की जानकारी ली गई। एसएसपी ने अधिकारियों को सुरक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन, रूट सैनिटाइजेशन, एंटी-सबोटेज जांच, क्विक रिस्पॉन्स टीमों की तैनाती, निगरानी व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र पर विशेष चर्चा की गई। एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस ने बताया कि प्रधानमंत्री जालंधर रवाना होने से पहले मुल्लांपुर का दौरा करेंगे। इसे देखते हुए मुल्लांपुर क्षेत्र और एयरपोर्ट जाने वाले मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहेगा। चंडीगढ़ से सटे मोहाली के इलाकों में भी पूरे दौरे के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की आवाजाही के दौरान कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाएगा और जरूरत के अनुसार अस्थायी प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए मोहाली और चंडीगढ़ पुलिस संयुक्त रूप से विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करेंगी।

नगर निगम मोहाली की हाउस मीटिंग में छाया रहा सफाई व्यवस्था का मुद्दा

पार्षदों ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, तुरंत समाधान की मांग

सागर पाहवा | मोहाली
समर न्यूज

नगर निगम मोहाली की नवनिर्वाचित टीम की दूसरी हाउस मीटिंग बुधवार को आयोजित हुई, जिसमें एजेंडे में शामिल सभी प्रस्ताव बहुमत से पारित कर दिए गए। हालांकि बैठक में प्रशासनिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई, लेकिन सदन में सबसे अधिक चर्चा शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर हुई। खास बात यह रही कि सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों के पार्षद इस मुद्दे पर एकमत दिखाई दिए और नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

बैठक के दौरान कई पार्षदों ने कहा कि शहर के विभिन्न वार्डों में समय पर कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, जिससे सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि मेयर द्वारा पदभार संभालते समय कुछ ही दिनों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात इसके विपरीत हैं। पार्षदों ने आरोप लगाया कि लोगों की लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा।

हाल ही में नगर निगम सीमा में शामिल किए गए गांवों के पार्षदों ने भी अपने क्षेत्रों की समस्याएं प्रमुखता से उठाईं। उनका कहना था कि इन गांवों में सफाई व्यवस्था बेहद खराब है और कई स्थानों पर नियमित रूप से झाड़ू तक नहीं लगती। उन्होंने आरोप लगाया कि जीएमएडीए यह कहकर जिम्मेदारी से बच रहा है कि क्षेत्र अब नगर निगम के अधीन हैं, जबकि नगर निगम का कहना है कि इन गांवों का औपचारिक हस्तांतरण अभी तक नहीं हुआ है। इस प्रशासनिक असमंजस का खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बैठक में एरो सिटी में बन रही ऊंची रिहायशी इमारतों का मुद्दा भी उठा। एक पार्षद ने फायर सेफ्टी नियमों के पालन को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि हाईराइज इमारतों में अग्निशमन व्यवस्थाओं की व्यापक जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने इस मामले में नगर निगम और संबंधित बिल्डरों की जवाबदेही तय करने की भी मांग की।

फेज-11 के पार्षद ने अपने क्षेत्र के कम्युनिटी सेंटर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह भवन लंबे समय से पुलिस के कब्जे में है। उन्होंने मांग की कि इसे खाली कराकर स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए। फेज-10 की पार्षद नीतू ने भी बैठक में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में विकास कार्यों और सफाई से जुड़े कार्यों में जानबूझकर बाधाएं डाली जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर के एक रिश्तेदार द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विकास कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिससे लोगों को बुनियादी सुविधाएं समय पर नहीं मिल पा रही हैं।

कुल मिलाकर, नगर निगम मोहाली की इस हाउस मीटिंग में भले ही सभी प्रस्ताव आसानी से पारित हो गए, लेकिन सफाई व्यवस्था, नव शामिल गांवों की समस्याएं, एरो सिटी की फायर सेफ्टी, कम्युनिटी सेंटर और विकास कार्यों में कथित हस्तक्षेप जैसे मुद्दों ने नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब देखना होगा कि प्रशासन और नगर निगम की नई नेतृत्व टीम इन मुद्दों के समाधान के लिए कितनी जल्द और प्रभावी कार्रवाई करती है।

सेक्टर-70 में अवैध पार्किंग का मुद्दा भी गूंजा

हाउस मीटिंग के दौरान सेक्टर-70 के पार्षद गुरजीत सिंह मामा ने अपने क्षेत्र में अवैध पार्किंग का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने कहा कि सेक्टर-70 स्थित निजी मॉल में आने वाले लोग अपनी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी कर देते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और स्थानीय निवासियों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस प्रशासन इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा। पार्षद ने मांग की कि सड़कों पर हो रही अवैध पार्किंग के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके और यातायात व्यवस्था सुचारु हो सके।

चंडीगढ़ में 79 व्यावसायिक संपत्तियों की ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू, 15 जुलाई से जमा होगी जमानत राशि

तीन सेक्टरों में स्थित बूथ व अन्य व्यावसायिक संपत्तियां होंगी नीलाम, पात्र व्यक्ति ऑनलाइन प्रक्रिया में ले सकेंगे हिस्सा

समर न्यूज। चंडीगढ़

चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर की 79 व्यावसायिक संपत्तियों की ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक व्यक्ति, फर्म, कंपनियां और अन्य पात्र संस्थाएं निर्धारित शर्तों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

प्रशासन ने बताया कि बोली में भाग लेने के लिए आवश्यक अर्जेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) और दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हो गई है। नीलामी पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धी बोली सुनिश्चित की जा सके। इस चरण में सेक्टर-46, सेक्टर-29 और सेक्टर-38 (वेस्ट) सहित तीन प्रमुख क्षेत्रों में स्थित बूथों और अन्य व्यावसायिक संपत्तियों को नीलामी के लिए रखा गया है। प्रशासन का उद्देश्य लंबे समय से खाली पड़ी सरकारी व्यावसायिक संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजस्व में वृद्धि करना है। इच्छुक बोलीदाताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और ईएमडी जमा करनी होगी।

एस्टेट कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, सभी संपत्तियों का आवंटन ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। सफल बोलीदाता को निर्धारित नियमों और भुगतान शर्तों का पालन करना होगा। प्रशासन ने इच्छुक आवेदकों से नीलामी में भाग लेने से पहले सभी नियम एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की अपील की है। इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और आवेदन प्रक्रिया एस्टेट कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

राजस्व बढ़ाने की तैयारी: चंडीगढ़ प्रशासन पिछले कुछ समय से खाली पड़ी सरकारी संपत्तियों के चरणबद्ध व्यावसायिक उपयोग की नीति पर काम कर रहा है। अधिकारियों का मानना है कि नियमित ई-नीलामी से न केवल सरकारी आय बढ़ेगी, बल्कि शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। हाल के महीनों में प्रशासन ने विभिन्न श्रेणियों की कई संपत्तियों की पहचान कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया है।

आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश: प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल वही बोलीदाता नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने निर्धारित समय के भीतर ईएमडी जमा कर दस्तावेजों का सत्यापन पूरा कराया होगा। सभी चरण ऑनलाइन होंगे और अंतिम आवंटन सबसे ऊंची वैध बोली के आधार पर किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि यदि किसी संपत्ति पर अपेक्षित प्रतिस्पर्धा नहीं मिलती है, तो उसे आगामी चरणों की ई-नीलामी में दोबारा शामिल किया जा सकता है।

बलौंगी में नौ ग्राम हेरोइन के साथ एनआरआई युवक गिरफ्तार, मामला दर्ज

समर न्यूज | मोहाली

मोहाली पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बलौंगी क्षेत्र से 9 ग्राम हेरोइन के साथ एक एनआरआई युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी गुप्त सूचना के आधार पर नशे की खेप की सप्लाई देने के लिए बलौंगी पहुंचा था।

पुलिस टीम ने जब आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो वह पुलिस को देखकर मौके से भाग निकला। हालांकि पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 9 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी की पहचान अनिल के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ थाना बलौंगी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

पीएम मोदी के दौरे से पहले मोहाली में हाई अलर्ट जारी

समर न्यूज | मोहाली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को प्रस्तावित दौरे को लेकर मोहाली पुलिस पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूतबनाने के लिए पांच जिलों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स सहित करीब 1500 जवानों की तैनाती की गई है। मुल्लांपुर रूट के लिए शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जाने वाले मार्ग और जिले के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी।

दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार को एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में जिले के सभी एसपी, डीएसपी, एसएचओ के अलावा सुरक्षा व्यवस्था में शामिल पड़ोसी जिलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़े सभी सुरक्षा पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की गई और संबंधित विभागों से तैयारियों की जानकारी ली गई।

एसएसपी ने अधिकारियों को सुरक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन, रूट सैनिटाइजेशन, एंटी-सबोटेज जांच, क्विक रिस्पॉन्स टीमों की तैनाती, निगरानी व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र पर विशेष चर्चा की गई।

समर न्यूज ब्रीफ

महज संदेह के आधार पर सरकारी अधिकारियों पर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की जा सकती: हाई कोर्ट

समर न्यूज, मोनिका रावत | चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक अधिकारियों पर ऐसे प्रतिकूल निष्कर्ष, जिनसे उनके सेवा जीवन या पेशेवर प्रतिष्ठा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता हो, केवल अनुमान या संदेह के आधार पर दर्ज नहीं किए जा सकते। अदालत ने कहा कि ऐसा तभी संभव है, जब रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री से उनके जानबूझकर किए गए कदाचार या कर्तव्य में जानबूझकर चूक का स्पष्ट प्रमाण हो। जस्टिस नीरजा के कलसन ने 2016 के दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए आरोपित की अपील स्वीकार करते हुए उसे संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। साथ ही जांच से जुड़े पुलिस अधिकारियों की तीन याचिकाएं भी मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों और उनसे जुड़े निर्देशों को निरस्त कर दिया।

एनएचएम टेंडर जांच में नया मोड़: दस्तावेजों के साथ जांच समिति के सामने पहुंचे देवेंद्र गौतम

समर न्यूज, मुकुल शर्मा | पंचकूला/सोनीपत : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), हरियाणा के अंतर्गत सोनीपत नागरिक अस्पताल से जुड़े दो चर्चित टेंडर मामलों की जांच में बुधवार को नया घटनाक्रम सामने आया। अन्याय के विरुद्ध–न्याय युद्ध मंच के संस्थापक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता देवेंद्र गौतम ने एनएचएम हरियाणा के निदेशक डॉ. जितेंद्र कादियान की अध्यक्षता में गठित जांच समिति के समक्ष उपस्थित होकर दोनों टेंडर मामलों से संबंधित दस्तावेज, रिकॉर्ड और अपना पक्ष विस्तार से प्रस्तुत किया। देवेंद्र गौतम ने बताया कि टेंडर आईडी: 2025_HRY_477781_1 और टेंडर आईडी: 2025_HRY_471938_1 से जुड़े सभी उपलब्ध दस्तावेज जांच समिति को सौंपे गए।

ट्रेड डील के विरोध में किसानों का शक्ति प्रदर्शन मोटरसाइकिल मार्च निकालकर सौंपा ज्ञापन

समर न्यूज, करुणा मित्तल | कालका : प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी ग्रुप) और शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने कालका क्षेत्र में मोटरसाइकिल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद किसानों ने कालका के सीटीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ट्रेड डील को किसानों और देश की कृषि व्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। किसानों का कहना था कि यदि बिना किसानों की सहमति के इस प्रकार की ट्रेड डील लागू की गई तो इसका सीधा असर देश के किसानों की आय, कृषि उत्पादों की कीमतों और खेती-किसानी पर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और किसी भी निर्णय से पहले किसान संगठनों से व्यापक संवाद करने की मांग की।

पानी से भरे गड्ढे ने छीन ली मजदूर की जिंदगी

मोहाली में बाइक फिसलने से 27 वर्षीय युवक की मौत, लोगों में बढ़ा रोष

- फेज-8बी इंडस्ट्रियल एरिया में हादसा
- तरनतारन निवासी युवक फैक्टरी से लौटते समय हुआ दुर्घटना का शिकार
- सड़कों की बदहाली पर उठे सवाल

समर न्यूज | मोहाली

बारिश के पानी से भरे गहरे गड्ढे ने एक और परिवार का सहारा छीन लिया। फेज-8बी इंडस्ट्रियल एरिया में मंगलवार शाम एक 27 वर्षीय फैक्टरी कर्मी की मोटरसाइकिल पानी में छिपे गड्ढे से टकराकर अनियंत्रित हो गई। सड़क पर गिरने से युवक के सिर में गंभीर चोट लगी।

उसे तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद एक बार फिर शहर की जर्जर सड़कों और मानसून के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतक की पहचान तरनतारन निवासी राजदीप सिंह (27) के रूप में हुई है। वह फेज-8बी स्थित एक पेंट फैक्टरी में कार्यरत था और बलोंगी में किराये के मकान में रह रहा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार राजदीप सिंह ड्यूटी खत्म कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। गुरु नानक स्वीट्स के पास सड़क पर बारिश का पानी जमा था। पानी के नीचे छिपे गहरे गड्ढे का अंदाजा न लगने से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़ा।

हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट आई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बारिश के दौरान सड़क पर पानी भरने से गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के लिए सफर बेहद खतरनाक हो जाता है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह पानी में छिपा गड्ढा सामने आया है। फिलहाल किसी विभाग या अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी किस एजेंसी की है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।

राजदीप सिंह परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और रोजगार की तलाश में मोहाली आया था। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गड्ढों को तत्काल भरने, जल निकासी व्यवस्था सुधारने और सड़क रखरखाव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो।

प्रधानमंत्री की जींद रैली के लाइव प्रसारण में पंचकूला के एससी समाज की होगी व्यापक भागीदारी

मुकुल शर्मा | पंचकूला
समर न्यूज

भाजपा अनुसूचित जाति (एससी) मोर्चा पंचकूला के जिला अध्यक्ष जसबीर सिंह जस्सा ने बताया कि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जींद रैली का लाइव प्रसारण सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष सभागार में किया जाएगा। इसे देखने के लिए जिले भर से अनुसूचित समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को सफल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए एससी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

रैली की तैयारियों के संबंध में आयोजित एससी मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक में भाजपा पंचकूला जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष रामपाल पाली सहित मोर्चा के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

वार्ड 41 की समस्याओं पर भाजपा पार्षद गुरप्रीत कौर उभा ने नगर निगम हाउस में बुलंद की अपनी आवाज

सागर पाहवा | मोहाली
समर न्यूज

भारतीय जनता पार्टी की पार्षद एवं वार्ड नंबर 41 की प्रतिनिधि गुरप्रीत कौर उभा ने नगर निगम की हाउस बैठक के दौरान अपने वार्ड से जुड़ी मूलभूत समस्याओं को से उठाया।

इसके साथ ही उन्होंने सफाई कर्मचारियों की चल रही हड़ताल को जल्द समाप्त कराने, उनकी जायज मांगों को तत्काल स्वीकार करने तथा उनकी समस्याओं का सम्मानजनक समाधान करने की मांग भी मेयर सरबजीत सिंह समाना और नगर निगम प्रशासन के समक्ष रखी।

बैठक के दौरान गुरप्रीत कौर उभा ने गांव संभालकी, नानू माजरा तथा सेक्टर-88 में लगे कूड़े के ढेर, गंदे पानी के जमाव, खराब सफाई व्यवस्था, बदहाल पार्कों तथा अन्य बुनियादी समस्याओं से संबंधित समाचार पत्रों की कतरनें और मौके की तस्वीरें हाउस में दिखाईं।

उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें मोहाली के विकास के दावों की वास्तविक स्थिति को उजागर करती हैं। उन्होंने कहा कि कई बार लिखित शिकायतें देने और अधिकारियों और मेयर के साथ बैठकें करने के बावजूद भी समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं किया गया। इसके कारण वार्ड के लोग आज भी सफाई, सीवरेज, गंदे पानी की निकासी, टूटी सड़कों, खराब स्ट्रीट लाइटों तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं।

कार्यक्रम | प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को होगी प्रकाशित

यूटी चंडीगढ़ में एसआईआर 2026 का गणना चरण पूरा

समर न्यूज | चंडीगढ़

यू.टी. चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर 2026 का गणना चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुश्री प्रेरणा पुरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह प्रक्रिया केंद्र शासित प्रदेश में सटीक, पारदर्शी और समावेशी निर्वाचक नामावली तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक चलाया गया। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा सभी पंजीकृत मतदाताओं को 100 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरित किए गए। कुल 5,16,427 पंजीकृत मतदाताओं में से 4,50,246 गणना प्रपत्र प्राप्त कर डिजिटाइज किए गए, जबकि 66,146 प्रपत्र बार-बार संपर्क के बावजूद प्राप्त नहीं हो सके। इस प्रक्रिया में 1,780 से अधिक बूथ लेवल एजेंटों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चंडीगढ़ में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के तहत मतदान केंद्रों की संख्या 614 से घटाकर 575 कर दी गई है। एसआईआर 2026 के तहत वर्तमान मतदाताओं को वर्ष 2002 की विशेष गहन पुनरीक्षण नामावली से जोड़ने का कार्य भी किया गया। प्राप्त प्रपत्रों में से 1,67,397 मतदाताओं ने स्वयं मैपिंग की, जबकि 2,13,398 मतदाता अपने माता-पिता के माध्यम से मैप किए गए। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई 2026 को प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 21 जुलाई से 18 सितंबर तक नोटिस चरण चलेगा। जिन मतदाताओं के प्रपत्रों में मैपिंग विवरण नहीं है या कोई विसंगति पाई गई है, उन्हें सत्यापन के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना विधिक प्रक्रिया, सुनवाई का अवसर और कारणयुक्त आदेश के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। जिन नागरिकों के नाम प्रारूप सूची में नहीं होंगे, वे 21 जुलाई से 20 अगस्त तक फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

उन्होंने पात्र नागरिकों से अपील की कि प्रारूप नामावली प्रकाशित होने के बाद अपना नाम अवश्य जांचें।

मोहाली में यूटीसीए की होनहार महिला क्रिकेटरों का हुआ सम्मान, मिले टेन एक्स यू क्रिकेट शूज

समर न्यूज, सागर पाहवा | मोहाली

: महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंगलवार को क्रिकेटरशॉप, मोहाली में आयोजित एक विशेष समारोह में यूनियन टेरिटरी क्रिकेट एसोसिएशन (यूटीसीए) की होनहार महिला क्रिकेटरों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को उनकी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए टेन एक्स यू की ओर से क्रिकेट शूज भेंट किए गए।

समारोह में यूटी क्रिकेट एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष संजय टंडन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि महिला क्रिकेट में अपार संभावनाएं हैं और ऐसे प्रयास उभरती प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को निरंतर मेहनत करने और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।

अमेरिका-ईरान टकरावः चौथे दिन भी एयरस्ट्राइक जारी; बम गिराए, ट्रंप ने दी बड़े हमलों की चेतावनी

सात घंटे तक सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा, ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, सैन्य कार्रवाई और तेज होने की आशंका

एजेंसी। वाशिंगटन/तेहरान।

अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार चौथे दिन भी बढ़ता रहा। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास स्थित कई सैन्य ठिकानों, रडार प्रणाली, ड्रोन अड्डों और मिसाइल क्षमताओं को निशाना बनाते हुए लंबे समय तक हवाई हमले किए।

अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और अमेरिकी हितों के खिलाफ किया जा रहा था। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तेहरान जल्द किसी समझौते की दिशा में नहीं बढ़ता, तो अगले सप्ताह हमलों का दायरा और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजलीघरों, पुलों और ऊर्जा ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि ईरान वार्ता के लिए तैयार होता है तो सैन्य कार्रवाई टाली जा सकती है।

अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के अनुसार ताजा अभियान कई घंटे तक चला, जिसमें लड़ाकू विमान, ड्रोन और नौसैनिक संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। हमलों का केंद्र दक्षिणी ईरान के वे इलाके रहे जिन्हें अमेरिका सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानता है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि कार्रवाई का उद्देश्य सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना था, नागरिक आबादी को नहीं। दूसरी ओर ईरानी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी हमलों में सैन्य और अन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई जारी रखने की बात कही।

▪ **बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमलेः** अमेरिकी कार्रवाई के कुछ ही समय बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। जॉर्डन ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने कई मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया, जबकि कुवैत में कुछ स्थानों पर नुकसान और आग लगने की खबरें सामने आईं। इन घटनाओं के बाद पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है।

▪ **ट्रम्प के निशाने पर पिकऐक्स माउंटेनः** राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक बार फिर ईरान के चर्चित पिकऐक्स माउंटेन का उल्लेख करते हुए संकेत दिया कि यह भी अमेरिकी सैन्य योजना का हिस्सा हो सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह इलाका नतांज परमाणु परिसर के निकट स्थित अत्यधिक सुरक्षित भूमिगत क्षेत्र माना जाता है, जहां संवेदनशील परमाणु या सैन्य गतिविधियां होने की आशंका लंबे समय से जताई जाती रही है। हालांकि ईरान इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।

▪ **होर्मुज शुल्क का फैसला बदलाः** तनाव के बीच ट्रम्प ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर प्रस्तावित 20 प्रतिशत शुल्क लगाने का अपना फैसला वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों के साथ निवेश और व्यापार सहयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बावजूद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री दबाव और सैन्य कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए हैं।

▪ **बढ़ी वैश्विक चिंताः** संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और तत्काल कूटनीतिक वार्ता शुरू करने की अपील की है। ऊर्जा बाजारों में भी तनाव का असर दिखाई दिया और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। यदि दोनों पक्ष वार्ता की मेज पर नहीं लौटते हैं तो सैन्य कार्रवाई और तेज हो सकती है।

ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थकों व मोदी समर्थकों में झड़प, नारेबाजी

▪ सतलुज फिल्म को लेकर शुरू हुई बहस के बीच भारतीय समुदाय के दो गुट आमने-सामने आए, पुलिस ने संभाला मोर्चा

एजेंसी। मेलबर्न

ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान खालिस्तान समर्थकों और भाजपा समर्थकों के बीच तीखी झड़प का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दोनों पक्ष एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते और धक्का-मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं। स्थिति बिगड़ने पर स्थानीय पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' और उससे जुड़े राजनीतिक विवाद को लेकर हुई। दोनों पक्षों के बीच पहले बहस हुई, जो बाद में हाथापाई तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मेलबर्न में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग एकत्र हुए थे। इसी दौरान कुछ स्थानों पर खालिस्तान समर्थकों ने प्रदर्शन किया, जबकि मोदी समर्थकों ने उनका विरोध किया। पुलिस ने समय रहते दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति पर नियंत्रण पा लिया।

किसी गंभीर घायल होने की सूचना नहीं है। स्थानीय प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है। घटना के बाद भारतीय समुदाय के विभिन्न संगठनों ने शांति बनाए रखने की अपील की है।

भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई की तैयारी

ट्रम्प ने रूस प्रतिबंध विधेयक का किया समर्थन; भारत और चीन जैसे देशों पर सख्त शुल्क की चर्चा

एजेंसी। वाशिंगटन

अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सीनेट में रूस पर प्रतिबंधों से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया है। इसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।

बिल के मुताबिक भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। यह बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के समर्थन से लाया जा रहा है। इसका मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है, ताकि उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो सके। रूस के अधिकारियों, शैडो टैंकर बेड़े, केंद्रीय बैंक और सरकारी ऊर्जा परियोजनाओं पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। पहले बिल के शुरुआती मसौदे में 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे 100% कर दिया गया।

अगर यह बिल पास हो जाता है, तो अमेरिका पहली बार किसी देश पर सिर्फ इसलिए टैरिफ लगाएगा, क्योंकि वह रूस से तेल खरीदकर उसकी कमाई बढ़ा रहा है। भारत ने जून 2026 में रूस से रिकॉर्ड 26.1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा, जो देश के कुल तेल आयात का 52.4% था। यानी पिछले महीने भारत में आयात होने वाले हर दो बैरल तेल में एक से ज्यादा बैरल रूस से आया।

रूस लगातार भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। मई के मुकाबले जून में रूस से तेल आयात में करीब 39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रूस से प्राकृतिक गैस खरीदने वाले चीन, फ्रांस, जापान, हंगरी और बेल्जियम को भी इसके दायरे में रखा गया है।

फ्रांस ने यूक्रेन में मिसाइल निर्माण को दी मंजूरी, रक्षा सहयोग को मिलेगी नई मजबूती

▪ यूक्रेन में ही बनेंगी क्रूज मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल और ग्लाइड बम; राफेल लड़ाकू विमान व नई वायु रक्षा प्रणाली के सौदे पर भी सहमति

एजेंसी। पेरिस

फ्रांस ने रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के साथ रक्षा सहयोग को बड़ा विस्तार देते हुए पहली बार अपने प्रमुख हथियारों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन की मंजूरी दे दी है। इसके तहत यूक्रेन अब अपने देश में ही फ्रांसीसी तकनीक से एससीएएलपी क्रूज मिसाइल, एस्टर-30 इंटरसेप्टर मिसाइल और एएएसएम (हैमर) प्रिसिजन ग्लाइड बम का उत्पादन कर सकेगा।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच हुई बैठक के बाद दोनों देशों ने रक्षा सहयोग का नया रोडमैप जारी किया। समझौते के तहत यूक्रेन ने 16 राफेल लड़ाकू विमानों और फ्रांको-इटालियन एसएएमपी/टी-एनजी वायु रक्षा प्रणाली की खरीद प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई है। फ्रांस का कहना है कि इससे यूक्रेन की हवाई सुरक्षा और रक्षा उत्पादन क्षमता दोनों मजबूत होंगी।

फ्रांसीसी सरकार के अनुसार यह व्यवस्था यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति पर निर्भरता कम करने और युद्ध के दौरान आवश्यक गोला-बारूद तथा मिसाइलों का उत्पादन तेज करने में मदद करेगी। एस्टर-30 मिसाइलें आधुनिक वायु एवं बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा हैं, जबकि एससीएएलपी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है।

यूरोप का संदेशः विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला केवल द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस के बढ़ते हमलों के बीच यूक्रेन के लिए यूरोपीय देशों के दीर्घकालिक समर्थन का संकेत भी है। हालांकि रूस ने पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को उन्नत हथियार और तकनीक उपलब्ध कराने पर पहले ही कड़ी आपत्ति जताई है। ऐसे में क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है।

वोटरों को लाखों डॉलर के चेक देना एलन मस्क पर पड़ सकता है भारी

एजेंसी। मैडिसन

अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क को चुनाव के दौरान मतदाताओं को 10-10 लाख डॉलर (10 लाख अमेरिकी डॉलर) के चेक देना महंगा पड़ सकता है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन चुनाव आयोग के द्विदलीय पैनल ने प्रारंभिक जांच में माना है कि मस्क ने राज्य के चुनावी कानून का उल्लंघन किया हो सकता है।

आयोग ने इस मामले में दो शिकायतें ब्राउन काउंटी के जिला अटॉर्नी कार्यालय को भेजते हुए संभावित आपराधिक जांच की सिफारिश की है। मामला वर्ष 2025 में विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट चुनाव के दौरान मस्क द्वारा कुछ मतदाताओं को 10-10 लाख डॉलर के चेक दिए जाने से जुड़ा है।

आरोप है कि इन भुगतानों का उद्देश्य मतदाताओं को प्रभावित करना था। मस्क और उनके समर्थित संगठनों ने उस चुनाव में रिपब्लिकन समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में करोड़ों डॉलर खर्च किए थे, हालांकि उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा।

▪ **40 दिन में होगा फैसलाः** चुनाव आयोग के अनुसार जिला अटॉर्नी कार्यालय अब मामले की समीक्षा करेगा और तय करेगा कि चुनावी रिश्वतखोरी या अन्य प्रावधानों के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाए या नहीं। नियमों के अनुसार अभियोजन पक्ष को निर्धारित अवधि के भीतर आयोग को अपनी कार्रवाई की जानकारी देनी होगी।

▪ **मस्क का पक्षः** मस्क पहले भी इस तरह के नकद पुरस्कार कार्यक्रमों का बचाव करते रहे हैं। उनका तर्क रहा है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आने वाला अभियान था।

हालांकि चुनावी पारदर्शिता से जुड़े संगठनों ने इसे मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। अब जिला अटॉर्नी के निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हैं।

16 साल बाद विश्व कप फाइनल में पहुंचा स्पेन, फ्रांस को 2-0 से हराकर रचा इतिहास

ओयारजाबाल ने पेनल्टी पर दिलाई बढ़त, पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल कर जीत पक्की की; अब खिताब के लिए इंग्लैंड या अर्जेंटीना से होगा मुकाबला

एजेंसी। डलास

स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराकर 16 साल बाद विश्व कप फाइनल में जगह बना ली। स्पेन ने पिछली बार 2010 में फाइनल खेलते हुए खिताब जीता था। पूरे मुकाबले में स्पेन ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और फ्रांस की मजबूत आक्रमण पंक्ति को प्रभावी प्रदर्शन का मौका नहीं दिया।

स्पेन को 22वें मिनट में बढ़त मिली, जब लामिन यामाल पर फ्रांस के लुकास डिन्ये के फाउल के बाद मिले पेनल्टी किक को मिकेल ओयारजाबाल ने गोल में बदल दिया। दूसरे हाफ के 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दानी ओल्मो के साथ बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए दूसरा गोल दागकर स्पेन की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी। फ्रांस की टीम, जिसमें किलियन एम्बाप्पे, उस्मान डेम्बेले और माइकल ओलीसे जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल थे, पूरे मैच में स्पेन की अनुशासित रक्षा पंक्ति को नहीं भेद सकी। स्पेन ने मिडफील्ड में भी दबदबा बनाए रखा और फ्रांस को सीमित अवसर ही दिए। मैच के बाद फ्रांस के मुख्य कोच डिडिएर डेशॉम्प और कप्तान एम्बाप्पे ने स्वीकार किया कि स्पेन बेहतर टीम साबित हुई और उसने जीत दर्ज की।

फाइनल पर नजर

इस जीत के साथ स्पेन अब विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से भिड़ेगा। लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद स्पेन को खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। टीम ने टूर्नामेंट में आक्रामक फुटबॉल के साथ-साथ मजबूत रक्षात्मक खेल का भी शानदार प्रदर्शन किया है।

फ्रांस का सपना टूटा

फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने का सपना पूरा नहीं कर सका। पूरे टूर्नामेंट में मजबूत प्रदर्शन करने वाली फ्रांसीसी टीम सेमीफाइनल में स्पेन के सामने बेअसर दिखी। अब फ्रांस तीसरे स्थान के मुकाबले में उतरेगा, जबकि स्पेन 16 साल बाद दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने की कोशिश करेगा।

पहले वनडे में भारत की दमदार जीत, इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर सीरीज में बनाई बढ़त

एजेंसी। बर्मिंघम

भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज की शानदार शुरुआत करते हुए पहले मुकाबले में मेजबान टीम को छह विकेट से हरा दिया। एजबेस्टन में खेले गए मैच में भारत ने 259 रन का लक्ष्य 45.2 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। यह जीत हाल में टी-20 श्रृंखला में मिली हार के बाद भारतीय टीम के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली रही।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 47.5 ओवर में 258 रन पर सिमट गई। जो रूट ने नाबाद 76 और लियाम डॉसन ने 68 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन अन्य बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना सके। भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाकर मेजबान टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका नहीं दिया। ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। तेज गेंदबाजों और स्पिनरों के संयुक्त प्रयास से भारत ने अंतिम ओवरों में इंग्लैंड की रनगति पर भी प्रभावी अंकुश लगाया।

259 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को कप्तान शुभमन गिल ने मजबूत शुरुआत दिलाई। उन्होंने 80 रन की आकर्षक पारी खेली, हालांकि ऐंठन के कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। इसके बाद अक्षर पटेल ने 57 रन और वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 52 रन की जिम्मेदार पारी खेलते हुए टीम को जीत तक पहुंचाया।

दोनों खिलाड़ियों ने छठे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी कर इंग्लैंड की वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का संतुलित प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया।

इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब दूसरा मुकाबला कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा, जहां इंग्लैंड श्रृंखला बराबर करने के इरादे से उतरेगा, जबकि भारतीय टीम जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगी।

विश्व कप की तैयारीः भारतीय टीम प्रबंधन इस सीरीज को 2027 एकदिवसीय विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रहा है। कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा कि टीम अलग-अलग संयोजनों को आजमा रही है और ऑलराउंडरों का शानदार प्रदर्शन भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है।

बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलित प्रदर्शन ने भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया है।

न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया, जेडेन लेनोक्स की घातक गेंदबाजी से बराबर हुई सीरीज

▪ बाएं हाथ के स्पिनर ने 19 रन देकर झटके पांच विकेट, टॉम लैथम और मार्क ब्रैसवेल ने जीत तक पहुंचाया

एजेंसी। जॉर्जटाउन

न्यूजीलैंड ने दूसरे एकदिवसीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हराकर शानदार वापसी की और पांच मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली।

प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बाएं हाथ के स्पिनर जेडेन लेनोक्स ने 19 रन देकर पांच विकेट चटकाए और मेजबान टीम की मजबूत शुरुआत को बड़े पतन में बदल दिया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने बिना विकेट खोए 63 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद पूरी टीम 36 ओवर में 138 रन पर सिमट गई। जॉन कैंपबेल ने सबसे अधिक 43 रन बनाए, जबकि लेनोक्स ने मध्यक्रम और निचले क्रम को लगातार झटके देकर मैच का रुख न्यूजीलैंड की ओर मोड़ दिया। यह उनके एकदिवसीय करियर का पहला पांच विकेट लेने का कारनामा भी रहा।

139 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड को भी शुरुआती झटके लगे और एक समय टीम 96 रन पर पांच विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद अनुभवी टॉम लैथम ने नाबाद 37 रन और मार्क ब्रैसवेल ने नाबाद 24 रन बनाकर छठे विकेट के लिए अटूट साझेदारी की तथा टीम को 32.4 ओवर में जीत दिला दी। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने एकदिवसीय क्रिकेट में अपनी 400वीं जीत भी दर्ज की।

व्यापार भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन के 99 प्रतिशत बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच; कपड़ा, चमड़ा और खाद्य उत्पादों को भी मिलेगा लाभ

भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता लागू, व्हिस्की, कारें व कई ब्रिटिश उत्पाद होंगे सस्ते

एजेंसी। नई दिल्ली

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) बुधवार से लागू हो गया। लगभग तीन वर्ष की बातचीत के बाद लागू हुए इस समझौते से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन के लगभग 99 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी, जबकि भारत चरणबद्ध तरीके से कई ब्रिटिश उत्पादों पर आयात शुल्क कम करेगा। इस समझौते का सबसे प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। ब्रिटेन से आयात होने वाली स्कॉच व्हिस्की, जिन, प्रीमियम कारें, लग्जरी वाहन, कुछ प्रकार के कपड़े, चॉकलेट, कॉस्मेटिक और चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद आने वाले वर्षों में पहले की तुलना में सस्ते हो सकते हैं। हालांकि अधिकांश वस्तुओं पर शुल्क में कमी एक साथ नहीं होगी, बल्कि तय समय-सीमा के अनुसार चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी।

दूसरी ओर भारत के कपड़ा, परिधान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, रत्न एवं आभूषण, कृषि-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और सेवा क्षेत्र को बड़ा निर्यात अवसर मिलेगा। उद्योग जगत का मानना है कि इससे भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। व्यापार समझौते के साथ ही सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी लागू हो गया है। इसके तहत सीमित अवधि के लिए ब्रिटेन में कार्यरत भारतीय पेशेवरों को दोनों देशों में एक साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। सरकार का मानना है कि इससे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं और अन्य पेशेवर क्षेत्रों के कर्मचारियों तथा कंपनियों को राहत मिलेगी।

व्यापार को मिलेगी नई रफ्तारः विशेषज्ञों के अनुसार यह समझौता केवल आयात-निर्यात तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश, सेवा क्षेत्र और तकनीकी सहयोग को भी मजबूती देगा। हालांकि कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को भी संरक्षण दिया गया है और कई शुल्क कटौतियां चरणबद्ध तरीके से लागू होंगी।

ग्लाडा की चुप्पीः शिव शक्ति कॉलोनी में अवैध प्लॉट कटे, सड़कें तक बनीं, कार्रवाई कोई नहीं

1 जुलाई को खबर प्रकाशित होने के बावजूद नहीं रुका काम; बिना मंजूरी कॉलोनियां विकसित, सड़कें बन रहीं, प्लॉटों की बिक्री जारी। लोगों ने उठाए मिलीभगत के सवाल

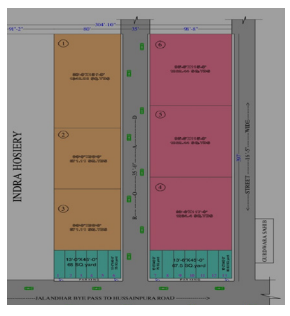

राहुल शर्मा | लुधियाना
समर न्यूज

1 जुलाई को हुसैनपुरा (मल्होत्रा पैलेस के पास) स्थित कथित अवैध कॉलोनी को लेकर खबर प्रकाशित होने के बाद भी ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (ग्लाडा) की कार्रवाई केवल आश्वासन तक सीमित दिखाई दे रही है। जिस कॉलोनी पर कार्रवाई का दावा किया गया था, वहां अब अंदरूनी सड़कों का निर्माण खुलेआम जारी है। वहीं, इससे सटी शिव शक्ति कॉलोनी में भी बिना आवश्यक मंजूरियों के प्लॉटों की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने ग्लाडा अधिकारियों की कार्यप्रणाली और मिलीभगत पर सवाल उठाए हैं।

▪ **15 दिन बाद भी नहीं दिखी कार्रवाईः** *1 जुलाई को श्री आत्म वल्लभ कॉलेज के सामने विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को लेकर मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया था। लेकिन करीब 15 दिन बीत जाने के बावजूद मौके पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके उलट कॉलोनी में विकास कार्य और तेज हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते निर्माण रुकवाया जाता तो कॉलोनी का स्वरूप इतना आगे नहीं बढ़ता।*

▪ **पहले सड़कें तैयार, फिर प्लॉट बेचने की तैयारीः** *मौके पर फिलहाल भवन निर्माण शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कॉलोनी को विकसित दिखाने के लिए तेजी से अंदरूनी सड़कें बनाई जा रही हैं। बिना स्वीकृत ले-आउट प्लान और सरकारी मंजूरी के खेतों में मिट्टी व कंक्रीट डालकर रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़कें तैयार होने के बाद इन प्लॉटों को फैक्ट्री और कमर्शियल उपयोग के नाम पर ऊंची कीमतों में बेचने की तैयारी की जा रही है।*

▪ **बुनियादी सुविधाओं का अभावः** *कॉलोनी में न सीवरेज नेटवर्क है, न पेयजल की व्यवस्था और न ही अन्य आवश्यक शहरी सुविधाएं। टाउन प्लानिंग के नियमों की अनदेखी कर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि भविष्य में यहां उद्योग स्थापित होते हैं तो गंदे पानी और औद्योगिक कचरे के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं होगी, जिससे आसपास के क्षेत्र में पर्यावरणीय संकट पैदा हो सकता है।*

▪ **शिव शक्ति कॉलोनी में भी बिना मंजूरी बिक रहे प्लॉटः** *हुसैनपुरा से सटी शिव शक्ति कॉलोनी में भी बिना आवश्यक स्वीकृतियों के प्लॉटों की बिक्री जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां भी नियमों की अनदेखी कर कॉलोनी विकसित की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, कॉलोनी को न रेरा की मंजूरी प्राप्त है और न ही ग्लाडा की आवश्यक स्वीकृतियां। इसके बावजूद खरीदारों को आकर्षित कर प्लॉट बेचे जा रहे हैं।*

▪ **सस्ते प्लॉट का लालच, सुविधाएं नदारदः** *स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में न पेयजल की समुचित व्यवस्था है, न सीवरेज नेटवर्क और न ही सरकारी मानकों के अनुरूप सड़कें विकसित की गई हैं। इसके बावजूद कम कीमत का लालच देकर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा है।*

▪ **अधिकारी जाते हैं, अगले दिन फिर शुरू हो जाता है कामः** *क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि अवैध निर्माण और बिजली के खंभे लगाए जाने की शिकायतें कई बार संबंधित विभागों को दी गईं, लेकिन कार्रवाई केवल औपचारिकता तक सीमित रही। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि अधिकारी मौके पर आते हैं, कुछ देर निरीक्षण करते हैं और लौट जाते हैं। अगले ही दिन निर्माण कार्य पहले की तरह शुरू हो जाता है।*

▪ **खरीदारों की जमा-पूंजी पर मंडरा रहा खतराः** *सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि कम कीमत के लालच में मध्यमवर्गीय परिवार अपनी जीवनभर की बचत ऐसे प्लॉटों में लगा देते हैं। बाद में यदि प्रशासन कार्रवाई करता है तो सबसे अधिक नुकसान खरीदारों को उठाना पड़ता है, जबकि कॉलोनी विकसित करने वाले पहले ही मुनाफा कमाकर निकल जाते हैं।*

▪ **निगम ने दिखाई सख्ती, ग्लाडा की चुप्पी पर सवालः** *हाल ही में नगर निगम ने अवैध निर्माण से जुड़े एक मामले में संबंधित अधिकारी को निलंबित कर सख्त कार्रवाई का संदेश दिया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि हुसैनपुरा और शिव शक्ति कॉलोनी में लगातार शिकायतों के बावजूद ग्लाडा अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया।*

▪ *ग्लाडा के मुख्य प्रशासक (सीए) **विकास हीरा** ने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि बिना मंजूरी वाली कॉलोनियों में संपत्ति खरीदने से बचें। ऐसी कॉलोनियों में ग्लाडा की ओर से पानी, सीवरेज, बिजली सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं। उन्होंने कहा कि निवेश से पहले ग्लाडा की वेबसाइट पर उपलब्ध अप्रूव्ड कॉलोनियों की सूची अवश्य देख लें।*

स्कूल में सीआईएससीई जोनल बैडमिंटन टूर्नामेंट-2026 का सफल आयोजन

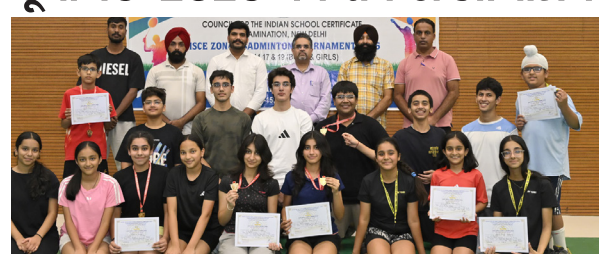

समर न्यूज | लुधियाना

सत पॉल मित्तल स्कूल, लुधियाना में 14 और 15 जुलाई 2026 को प्रतिष्ठित मित्तल ऑडिटोरियम में सीआईएससीई जोनल लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का सफल आयोजन किया गया। दो दिनों तक चले इस टूर्नामेंट में लुधियाना जोन के विभिन्न स्कूलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया व अपने शानदार खेल, मेहनत, अनुशासन तथा खेल भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया।

मेजबान स्कूल के अलावा, इस प्रतियोगिता में लुधियाना जोन के विभिन्न सीआईएससीई स्कूलों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ-साथ निष्पक्ष खेल, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने का एक शानदार अवसर बनी। अंडर-19 सीनियर लड़के वर्ग में सत पॉल मित्तल स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि बी.बी. एस.बी. कॉन्वेंट स्कूल, सिधवां बेट उपविजेता रहा।

अंडर-19 सीनियर लड़कियां वर्ग में सत पॉल मित्तल स्कूल ने चैंपियनशिप अपने नाम की, जबकि सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, सेक्टर-39 उपविजेता रहा। अंडर-17 जूनियर लड़के वर्ग में सत पॉल मित्तल स्कूल ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, सेक्टर-39 दूसरे स्थान पर रहा।

जीरो में मिला ठेका, लाखों की अवैध वसूली, मुफ्त सुविधाओं पर ले रहे पैसे

लक्की मेहता | लुधियाना
समर न्यूज

हैबोवाल और दुगरी की हफ्तावार मंडियों में फड़ी लगाने वाले सैकड़ों दुकानदारों से कथित तौर पर नियमों

को ताक पर रखकर लाखों रुपये की अवैध वसूली की जा रही है। मार्केट कमेटी द्वारा एवीए एसोसिएट को दिया गया ठेका भले ही जीरो कीमत पर आवंटित हुआ हो, लेकिन मंडी में फड़ी लगाने वाले दुकानदारों का आरोप है कि ठेकेदार ने मुफ्त और निर्धारित सुविधाओं के नाम पर रोजाना हजारों रुपये की अतिरिक्त वसूली का समानांतर सिस्टम खड़ा कर रखा है। दुकानदारों का कहना है कि डीएनआईटी की शर्तों के मुताबिक टेबल का शुल्क 25 रुपये और छतरी का 15 रुपये तय है, जिस पर 18 प्रतिशत जीएसटी अलग से लागू होता है। वहीं सफाई, पार्किंग और सिक्योरिटी जैसी सुविधाएं पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराई जानी हैं।

ठेकेदार टेबल के 30 रुपये, छतरी के 30 रुपये, सफाई के 30 रुपये, सिक्योरिटी के 30 रुपये, पार्किंग के 10 रुपये व लाइट के नाम पर 30 रुपये अलग से वसूल रहा है। आरोप है कि मंडी में जनरेटर लगाने की अनुमति न होने के बावजूद जनरेटर चलाया जा रहा है। हर फड़ी वाले से बिजली के नाम पर अलग से पैसे लिए जा रहे हैं।

महाआरती कर रथयात्रा में करुणा व कृपा बरसाने की प्रार्थना

लक्की भट्टी | लुधियाना
समर न्यूज

भगवान जगन्नाथ जी की 30वीं ऐतिहासिक एवं विशाल रथयात्रा से पूर्व बुधवार को इस्कॉन एवं भगवान जगन्नाथ रथयात्रा महोत्सव कमेटी की ओर से महाराजा ग्रैंड में भव्य महाआरती एवं मंगल प्रार्थना समारोह का आयोजन किया गया।

इस विशेष आयोजन में महानगर के 151 प्रतिष्ठित एवं सौभाग्यशाली यजमान परिवारों ने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा की विधिवत महाआरती कर प्रभु से 16 जुलाई को रथ पर सवार होकर समस्त नगर वासियों पर करुणा, कृपा व आशीर्वाद बरसाने की प्रार्थना की।

▪ **भक्ति, श्रद्धा और उल्लास से गूंजा महाराजा ग्रैंडः** महाआरती के दौरान संपूर्ण वातावरण भगवान जगन्नाथ के जयघोष, भजन-कीर्तन और हरिनाम संकीर्तन से भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर प्रभु के श्रीचरणों में सुख, शांति, समृद्धि एवं विश्व कल्याण की कामना की। आयोजन में उपस्थित सभी यजमान परिवारों ने रथयात्रा के सफल एवं भव्य आयोजन के लिए भी मंगलकामनाएं अर्पित कीं।

▪ **श्री दुर्गा माता मंदिर से शाम 4 बजे प्रारंभ होगी रथयात्रा : संजीव सूद बांका...** रथयात्रा महोत्सव कमेटी के चेयरमैन राजेश ढांडा व महासचिव संजीव सूद बांका ने बताया कि 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी की 30वीं विशाल एवं ऐतिहासिक रथयात्रा श्री दुर्गा माता मंदिर से शाम 4 बजे प्रारंभ होगी। रथयात्रा क्लब रोड, फव्वारा चौक, रानी झांसी रोड और घुमार मंडी से होते हुए आरती चौक पहुंचेगी, जहां धार्मिक कार्यक्रमों के साथ इसका समापन होगा। कमेटी ने समस्त श्रद्धालुओं से रथयात्रा में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ के दिव्य दर्शन का आग्रह किया।

▪ **सिद्धपीठ महाबली संकटमोचन श्री हनुमान मंदिर रानी झांसी रोड पर करेगा रथयात्रा का भव्य स्वागत : अमन जैन...** सिद्धपीठ महाबली संकटमोचन श्री हनुमान मंदिर जोशी नगर के प्रधान अमन जैन, चेयरमैन ऋषि जैन, उप प्रधान अनुज मदान, सैक्रेटरी सौरव जैन ने जगन्नाथ सेवकों की ओर से दिए गए निमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ जी अति कृपालु और दयालु हैं| जो भी भक्त उनके स्वागत एवं उनके भक्तों की सेवा के लिए मंच लगता है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है।

फैक्ट्री में 19 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू

समर न्यूज | लुधियाना

पंजाब के औद्योगिक शहर लुधियाना में बाल श्रम के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के दौरान एक फैक्ट्री से 19 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया गया। जिला प्रशासन, श्रम विभाग, पुलिस और बाल संरक्षण इकाइयों की संयुक्त कार्रवाई में यह खुलासा हुआ कि बच्चों से फैक्ट्री में काम कराया जा रहा था। मामले में दो फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

छापेमारी के दौरान सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर उनकी चिकित्सकीय जांच कराई गई। इसके बाद उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां से उनके पुनर्वास और परिवारों से संपर्क की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अधिकांश बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं और उन्हें श्रम में लगाया गया था। प्रशासन यह भी जांच कर रहा है कि कहीं इस मामले के पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो सक्रिय नहीं था।

पुलिस और श्रम विभाग फैक्ट्री के दस्तावेजों, कर्मचारियों के रिकॉर्ड और बच्चों को काम पर रखने की परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में मानव तस्करी या अन्य गंभीर अपराध के प्रमाण मिलते हैं तो संबंधित धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। प्रशासन ने शहर की अन्य औद्योगिक इकाइयों में भी इसी प्रकार के औचक निरीक्षण जारी रखने की बात कही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नहरी प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश

लक्की भट्टी | लुधियाना
समर न्यूज

विश्व बैंक और एआईआईबी के सहयोग से तैयार की जा रही लुधियाना सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम की प्रगति की समीक्षा के लिए डिस्प्यूट एडजुडिकेशन बोर्ड का तीसरा दौरा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

दो दिन तक चली समीक्षा के दौरान परियोजना की प्रगति, अनुबंध प्रबंधन और कार्य में तेजी लाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मेयर प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर ने डीएबी के चेयरमैन लियोन लैम्ग्रेक्ट, सदस्य ट्रंग गुयेन और तिलक कोलोने के साथ बैठक कर परियोजना की मौजूदा स्थिति पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और तय समय पर परियोजना पूरी करने के निर्देश दिए।

पहले दिन डीएबी की टीम ने गांव बिलगा स्थित 580 एमएलडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, प्रमुख ट्रांसमिशन पाइपलाइन कॉरिडोर व विभिन्न ओवरहेड सर्विस रिजर्वायर निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। दूसरे दिन नगर निगम, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, सलाहकारों और कार्यदायी एजेंसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई।

आस्था

दिव्य सिद्ध श्री बालाजी दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब

भक्तों की आस्था का केंद्र सिद्ध पीठ महाबली संकटमोचन श्री हनुमान मंदिर : अमन/अनुज

भजन गायक का सम्मान करते अमन जैन, ऋषि जैन, अनुज मदान और अन्य।

लक्की भट्टी | लुधियाना
समर न्यूज

सिद्ध पीठ महाबली संकटमोचन श्री हनुमान मंदिर, जोशी नगर धाम, शंकराचार्य नगर में साप्ताहिक संध्या चौंकी का भव्य एवं दिव्य आयोजन मंदिर प्रधान अमन जैन, चेयरमैन ऋषि जैन एवं उपप्रधान अनुज मदान की अध्यक्षता में श्रद्धा, भक्ति एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दिव्य सिद्ध दरबार में विराजमान श्री बालाजी महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। संध्या चौंकी में प्रसिद्ध भजन गायक राजवीर राज (बरनाला) ने अपनी मधुर वाणी से श्री बालाजी महाराज की महिमा का गुणगान करते हुए एक से बढ़कर एक मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों पर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूम उठे और पूरा मंदिर परिसर "जय श्री बालाजी" एवं "जय श्री राम" के जयघोषों से गूंज उठा।

मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से राजवीर राज एवं उनकी पूरी टीम को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्री सालासर धाम एवं श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम के पावन छिटे श्रद्धालुओं पर किए गए तथा श्री बालाजी महाराज के समक्ष पवित्र ध्वज फहराकर विश्व कल्याण, सुख-समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की गई। अंत में सामूहिक श्री हनुमान चालीसा पाठ के साथ संध्या चौंकी का विधिवत समापन हुआ तथा सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

मंदिर प्रधान अमन जैन,चेयरमैन ऋषि जैन मंदिर के उपप्रधान अनुज मदान ने कहा कि आज सिद्ध पीठ महाबली संकटमोचन श्री हनुमान मंदिर की ख्याति पूरे विश्वभर में फैल चुकी है। प्रतिदिन दूर-दराज के राज्यों एवं विदेशों से श्रद्धालु लंबी-लंबी कतारों में लगकर दिव्य सिद्ध दरबार में विराजमान भगवान श्री बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं तथा श्रद्धापूर्वक सवा मनी का भोग अर्पित करते हैं। श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा से हजारों भक्त अपनी झोली भरकर लौटते हैं, जिसकी साक्षी प्रतिदिन मंदिर में उमड़ने वाली विशाल श्रद्धालुओं की भीड़ स्वयं है।

इस अवसर पर प्रधान अमन जैन,चेयरमैन ऋषि जैन,उपप्रधान अनुज मदान, सौरव जैन, सोमनाथ मड़कन, ज्योति गुप्ता, संजय गुप्ता, अरविंद टिल्लू, नरिंदर नथानी, राहुल हांडा, संदीप पब्बी, सतीश डंग, रोहित डंग, पुनीत शर्मा, संदीप धमीजा, भारती सोनी, वेद लूथरा, अनिल जैन, गीतांश गांधी, देवांश जैन, अश्वनी मग्गू, सन्नी सतीजा, प्रतीक सोहर, विवेक शर्मा, मनीष अरोड़ा सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे।

ग्रुप एडिटरः अर्शदीप सिंह। एग्जीक्यूटिव एडिटर : नितिन उपमन्यु । मुद्रक, प्रकाशक, इंप्रेशन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट- 22, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, पंचकूला। *समाचार चयन के लिए PRP एक्ट के तहत जिम्मेदार। सभी विवादों का न्यायाधिकार क्षेत्र लुधियाना होगा। RNI No. CHMUL/25/A1155